साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-28 अंक- 46 14 - 20 नवंबर 2021 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

कुदरत का क़हर और सबक़
पृष्ठ-6

कैसे मिले भुखमरी से मुक्ति
पृष्ठ-7

हिंसा और हिंसा के लिए उकसाने से कमज़ोर हो रही है

राष्ट्रीय एकता

देश के शांति प्रिय नागरिकों के लिए एक सोच का विषय

भारत में हिंसा और उग्रता में बढ़ोत्तरी केवल और केवल आम नागरिकों की चुप्पी से ही बढ़ रही है, जिससे देश की एकता और अखंडता कमज़ोर पड़ रही है? आख़िर इसका इलाज क्या है?

हाल के सालों में समाज में हिंसक घटनाएं जिस तेज़ी से बढ़ी हैं, उससे लगता है कि हर तरफ हिंसा, क्रोध, भय, असत्य और आक्रामकता का न केवल वर्चस्व स्थापित हुआ है बल्कि उनको वैधता भी मिल रही है। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इस तरह की घटनाओं को सामान्य मान कर नज़रअंदाज़ किए जाने की प्रवृत्ति भी तेज़ी से बढ़ी है। समाज और प्रशासन दोनों ही स्तरों पर यह देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी ने हिंसा को परिभाषित करते हुए कुविचार, मिथ्या, द्वेष, किसी का बुरा चाहना, जातिगत विद्वेष आदि सब हिंसा का ही रूप बताया था। साथ ही यह भी कि संसार के लिए जो वस्तु आवश्यक है उस पर कब्ज़ा रखना भी हिंसा है। लेकिन आज हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनकी चर्चा इस संदर्भ में की जा सकती है।

समाज में समय-समय पर हिंसा के कई स्वरूप उभरते रहे हैं, ग़रीबी, निरंतर उत्पीड़न और हताशा के कारण उत्पन्न होने वाली हिंसा, हम बनाम वे और इसका हिंसा से संबंध, पुलिस के व्यवहार के प्रति आक्रोश और हिंसा इत्यादि। घर परिवारों के भीतर निजी संबंधों में मनमुटाव के कारण होने वाली हिंस, परिवार में संपत्ति व प्रभुत्व के लिए हिंसा इत्यादि भी इसके रूप और कारण हैं, जिन्होंने औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाओं को या तो तोड़ दिया है या फिर टूटने के कगार पर पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, राजनीतिक, प्रशासनिक और धन-बल का उपयोग करके झूठे मुक़दमे दायर करना भी हिंसा का ही रूप हे। इस प्रकार की हिंसा समाज को प्रतिशोध की ओर धकेलती है। यह भी एक तथ्य है कि भ्रष्टाचार हमेशा से ही हिंसा का एक रूप रहा है। छोटी सी बात पर जान ले लेने, निजी रिश्तों में संदेह के आधार पर मारपीट व हत्या, प्रेम-प्रसंग या जाति के इतर विवाह करने पर हत्या कर देने जैसी घटनाएं अब जैसे सामान्य बात हो गई है इसलिए हिंसा किसी भी प्रकार की क्यों न हो, समाज के विकास और प्रगति में बाधा ही उत्पन्न करती है। इसलिए यह कहना ग़लत नहीं होगा कि आज देश लोकतंत्र, खुशहाली, मानव विकास, लैंगिग समानता आदि के वैश्विक सूचकांकों में निम्न स्तर पर बना हुआ है तो उसके मूल कारण भी कहीं न कहीं बढ़ती हिंसक प्रवृत्तियों में मौजूद हैं।

देश में 'हमारी संस्कृति' और 'उनकी संस्कृति' के प्रश्न इतने महत्वपूर्ण और गंभीर पहले कभी नहीं हुए, जितने वर्तमान दौर में देखने को मिल रहे हैं। समूचा संचार माध्यम इन पक्षों पर केन्द्रित दिख रहा है। देखने में आ रहा है कि परपंरा को गर्व के साथ जोड़कर अनेक व्यक्ति या समूह अपने क्रोध एवं अपनी आक्रामकता को पेश करने में गौरव समझ रहे हैं।

हाल के दिनों में जिस तरह की हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं वे और ज़्यादा गंभीर है। मसलन, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों को एक काफिले की गाड़ियों ने कुचल दिया। आरोप है कि इनमें एक वाहन एक मंत्री पुत्र का था। प्रतिशोध में हिंसा भड़क उठी और चार और लोग मारे गए। देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाएं बताती हैं कि हमने महिलाओं के सम्मान को ख़त्म कर डाला है। चुनावी हिंसा की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा ने लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के अहम प्रश्न को एक बार फिर खड़ा कर दिया है। अल्पसंख्यकों और दलितों के विरुद्ध बढ़ती हिंसा समाज में बढ़ती विघटन की प्रवृत्ति का प्रमाण है। हिंसा की तमाम ऐसी घटनाएं एक आध्यात्मिक एवं शांति प्रिय समाज को हिंसक समाज में परिवर्तित करने पर उतारू है। आतंकवाद की बात करें तो आज यह समस्या वैश्विक हिंसा के सबसे भयावह रूप में मौजूद हैं और दुनिया के ज़्यादातर देश इससे त्रस्त हैं। प्रश्न यह है कि क्या आतंकवाद को ताक़त से ही समाप्त किया जा सकता है? विवेक सम्मत जवाब तो यही होगा कि कदापि नहीं। अगर ऐसा हो सकता तो दुनिया से आतंकवाद, उग्रवाद या अपराध कब के समाप्त हो चुके होते। कहने को तमाम देश आतंकी संगठनों के ख़िलाफ़ अभियान चला रहे हैं, लेकिन यह समस्या ख़त्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है।

भारत एक बहु-संस्कृति वाला राष्ट्र रहा है। देश में 'हमारी संस्कृति' और 'उनकी संस्कृति' के प्रश्न इतने महत्वपूर्ण और गंभीर पहले कभी नहीं हुए, जितने वर्तमान दौर में देखने को मिल रहे हैं। समूचा संचार माध्यम इन पक्षों पर केन्द्रित दिख रहा है। देखने में आ रहा है कि परपंरा को गर्व के साथ जोड़कर अनेक व्यक्ति या समूह अपने क्रोध एवं अपनी आक्रामकता को पेश करने में गौरव समझ रहे हैं। वस्तुतः परंपरा की गर्व के साथ स्वीकृति कुछ लोगों या समूहों में हिंसा की उपस्थिति का परिचायक है जो उनके विचारों, चर्चा और उनकी गतिविधियों में उभरकर आता है। यह स्थिति उन व्यक्तियों में धीरे धीरे ऐसा सत्तावादी चरित्र

बाक़ी पेज 11 पर

कासंगज में अल्ताफ़ की हिरासती मौत की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएं : मौलाना महमूद मदनी

कासगंज : (उ॰ प्र॰) : 22 वर्षीय अल्ताफ की मौत पर दुख और और घटना की सही जानकारी हेतु जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के एक प्रतिनिधिमंडल ने कासगंज का दौरा किया। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। अध्यक्ष महोदय ने यूपी सरकार से इस घटना की न्यायिक जांच काराने और संलिप्त दोषी पुलिसकर्मियों को कठोर सज़ा की मांग की और इस घटना की जांच एक उच्चस्तरीय कमेटी से कराने, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये के मुआवज़े की रक़म देने की मांग की। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारे देश की पहचान हमेशा मानवाधिकारों के संरक्षण जैसे मूल्यों पर आधारित रही है, यदि कोई सरकार इन नियमों को बनाए रखने में विफल रहती है तो वहां इससे बड़ी कोई विफलता नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिन्द शोक संतप्त माता-पिता के साथ खड़ा है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एक प्रतिनिधिमंडल ने जनरल सेक्रेट्री मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी के नेतृत्व में कासगंज का दौरा किया और पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिले। इस प्रतिनिधिमंडल ने कासगंज के डीएम और एसपी से मुलाक़ात की और अल्ताफ को न्याय दिलाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मिलकर सान्त्वना दी और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जमीयत के इस प्रतिनिधिमंडल में मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी, मौलाना मुहम्मद यासीन, डॉ. अज़र अली, मुफ्ती मौ. ख़बीब अध्यक्ष जमीयत उलेमा कासगंज, मौलाना मोहम्मद असरारुल्लाह सचिव जमीयत उलेमा कासगंज और क़ारी मोहम्मद राशिद अध्यक्ष जमीअत उलेमा तहसील सहावर कासगंज भी शामिल थे।

पाकिस्तान में फौजी चौधराहट सेना के आगे सरकार बेबस

विभूति नारायण राय

इस बार पाकिस्तान में कौन सा फार्मूला चलेगा, जहांगीर करामत वाला या परवेज़ मुशर्रफ़ वाला? जब पाकिस्तान के प्रसिद्ध स्तंभकार, पत्रकार और क्रिकेट प्रशासक नजम सेठी अपने एक कार्यक्रम में सवाल पूछते हैं, तब उनके सामनु पुराने अनुभवों पर आधारित कुछ ठोस कारण हैं। पाकिस्तान के जन्म के साथ ही देश की राजनीति में फौज के निर्णायक हस्तक्षेप की परंपरा पड़ गई थी और अब तो यह संस्थाबद्ध हो गई है। जब मार्शल लॉ नहीं होता है, तब भी विदेश और रक्षा संबंधी मसलों पर अंतिम फैसला तो सेना का ही होता है।

कई बार जनता से चुनी सरकारों के प्रतिनिधियों को गलतफहमी हो जाती है कि दूसरे लोकतंत्रों की तरह उनके मुल्क में भी 'सिविल बालादस्ती' या नागरिक श्रेष्ठता का सिद्धांत काम करता है, जिसमें सेना चुनी हुई सरकार के अधीन काम करती है। सारे फैसले सरकार लेती है और सेना नौकरशाही के दूसरे अंगों की तरह उसे लागू करती है। इसी ग़लतफहमी से यह दुविधा उत्पन्न होती है, जिसका ज़िक्र ऊपर नजम सेठी के इंटरव्यू में आया है। एक ज़माने में खुद सेना की निर्मित रहे नवाज़ शरीफ़ ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सिविल बालादस्ती की बात शुरू कर दी थी। सेनाध्यक्ष जनरल जहांगीर करामत ने जब एक ऐसा बयान दे दिया, जो प्रधानमंत्री को नागवार लगा, तो उन्हें तलब करके उनका इस्तीफ़ा मांग लिया गया। बावजूद इसके कि उनके कई जनरल सरकार का तख़्ता पलटने के पक्ष में थे, जहांगीर करामत इस्तीफा देकर चुपचाप घर चले गए। यह वही दांव तब उल्टा पड़ गया, जब 1999 में नवाज़ शरीफ़ ने अपने एक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ को बर्खास्त किया, तो सेना के वरिष्ठ ने उन्हें ही अपदस्थ कर मार्शल लॉ लगा दिया।

नजम सेठी या दूसरे राजनैतिक विश्लेषक पिछले कई दिनों से सांस रोके राष्ट्र को उस संकट से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोर कमांडरों की एक बैठक में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की नई नियुक्तियों के संबंध में लिए गए निर्णयों से उत्पन्न हुआ है। पाकिस्तान की ज़मीनी हक़ीक़त जानने वाले जानते हैं कि कोर कमांडरों की सीमित कई मामलों में केन्द्रीय मंत्रिमंडल से भी अधिक ताक़तवर होती है। इस समिति ने आधे दर्जन से अधिक कोर कमांडरों को इधर से उधर किया, तब तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने इमरान के पसंदीदा आईएसआई प्रमुख जनरल फैज़ जमीद को भी बदल डाला और वह भी बिना प्रधानमंत्री से पूछे। नवनियुक्त आईएसआई प्रमुख को अपना कार्यभार संभालने के पहले प्रधानमंत्री की सहमति की दरकार है और यहीं पर पेंच फंसा है।

पाकिस्तान में जहां चार बार घोषित और कई बार अघोषित मार्शल लॉ लग चुके हैं,वहां एक अलिखित परंपरा है कि डीजी आईएसआई प्रधानमंत्री अपनी मर्ज़ी और पसंद से लगाते रहे हैं। परंपरा के अनुसार, सेना मुख्यालय तीन से चार लेफ्टिनेंट जनरलों के नाम प्रधानमंत्री के पास भेजता है और उनमें से किसी एक पर सहमति के साथ फाइल वापस आ जाता है। इस बार यह परंपरा तोड़ दी गई और कोर कमांडरों ने ही वर्तमान डीजी आईएसआई जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया डीजी आईएसआई लगा दिया। परछे के पीछे क्या हुआ, पूरा तो किसी को नहीं पता, पर इतना छन-छनकर बाहर आ गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ इमरान ख़ान के बहुत करीब हो गए थे और यही सैन्य नेतृत्व को खटक रहा था। जनरल फैज़ वही अधिकारी हैं, जिनकी तस्वीर पिछली सरकार में एक चरमपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं का धरना ख़त्म कराते समय मुद्रा बांटते हुए मीडिया में छपी थी।

सार्वजनिक तौर पर तो फौजी नेतृत्व कह रहा हे कि फैज़ हमीद ने अभी तक कोई कोर कमांड नहीं की है और अगले वर्ष जब वह अगले सेनाध्यक्ष की दौड़ में होंगे, तब यह तथ्य उनके ख़िलाफ़ जा सकता है, हक़ीक़त इसके उलट है। सेना प्रमुख जनरल बाजवा और उनके करीबी जनरल साहबान फैज़ हमीद और इमरान ख़ान की निकटता को शक की निगाह से देखने लगे थे। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान

बाक़ी पेज 11 पर

दुनिया की ईवी कैपिटल बनेगी दिल्ली

कैलाश गहलोत

प्रश्नः- राजधानी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल (ईवी) कैपिटल बनाने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। योजना के परिणाम कैसे हैं और सरकार का टारगेट क्या है?

उत्तरः- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सपना बहुत बड़ा है। वह दिल्ली को देश ही नहीं, दुनिया की ईवी कैपिटल बनाने की तैयारी करके चल रहे हैं। हमने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाँच की। इसके लिए हमने सभी संबंधित एजेंसियों और लोगों से बातचीत करके सारा ख़ाका तैयार किया ताकि इस नीति को अपनाने और उस पर काम करने में कोई दिक्कत न हो। इसी का परिणाम है कि दिल्ली में एक-डेढ़ वर्ष में हुए वाहन रजिस्ट्रेशंस में 4.5 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन हुए। सबसे बड़ी बात ई-वाहनों रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स माफ है। इसके अतिरिक्त हम विभिन्न वाहनों पर अलग अलग सब्सिडी भी दे रहे हैं।

प्रश्नः- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुविधाएं और संसाधन किस तरीके से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या योजना है?

उत्तरः- भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अगर सोलर एनर्जी से जोड़ दिया जाए तो यह और भी अच्छा होगा पर्यावरण संरक्षण के लिहाज़ से यह काफी अच्छा रहेगा। हम चार्जिंग स्टेशन, बैटरी और अन्य सुविधाओं पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। फोर व्हीलर के संग टू व्हीलर्स पर भी सब्सिडी है। किसी भी व्यक्ति को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं हैं ऑनलाइन सिस्टम के तहत सब्सिडी का पैसा वाहन खरीदने वाले के खाते में पहुंच जाता है। यही नहीं यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर चार्जिंग स्टेशन लगवाना चाहता है तो 6000 रुपए की सब्सिडी भी मिलती है। इस स्टेशन के लिए बिजली भी घरेलू बिजली कीमत से कम पर उपलब्ध कराई जाती है। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को लेकर सरकार तेज़ी से काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंट स्टेशन बनाया जाए। करीब 80 चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं और बड़ी संख्या में अन्य स्टेशन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली में जो भी पार्किंग हैं उनके भीतर 5 प्रतिशत जगह चार्जिंग स्टेशन के लिए फिक्स करने को लेकर भी प्लान बनाया गया है।

प्रश्नः- दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने के बाद प्रदूषण के स्तर पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा..?

उत्तरः- रिसर्च के परिणाम और जो डाटा हमारे पास है उसके अनुसार करीब 20 प्रतिशत प्रदूषण जो दिल्ली में है वह विभिन्न तरीके के डीजल पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के धुएं से होता है। यदि यह वाहन पूरी तरह से हट जाएं तो साफ है कि राजधानी से 20 प्रतिशत प्रदूषण कम हो जाएगा।

प्रश्नः- दिल्ली सरकार बड़ी संख्या में बसें खरीद रही है, इसको लेकर विपक्ष घोटाले का आरोप लगाता रहा है, इसमें क्या कहना है आपका?

उत्तरः- केन्द्र की जांच में किसी तरह की कोई खामी नज़र नहीं आई। फिर भी विपक्ष जब भी चाहे जांच करा सका है। हम साफ नीयत व पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। बाकी विपक्ष को तो धर्म है आरोप लगाना। हमारा तो प्रयास यही है कि दिल्ली के लोगों को अच्छे से अच्छा

बाक़ी पेज 11 पर

दिल्ली : पार्षदों के प्रदर्शन में आई गिरावट

कोरोना काल में जब लोगों को जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत थी, तब तीनों नगर निगमों के पार्षद उम्मीद के मुताबिक सक्रिय नहीं थे। ऐसे में जब अगले वर्ष निगमों के चुनाव होने हैं, पार्षदों के प्रदर्शन में आई गिरावट की रिपोर्ट पार्टियों की चिंता बढ़ाने वाली है। किसी भी पार्षद ने 'ए' श्रेणी (80 से 100 फीसदी के बीच) का प्रदर्शन नहीं किया हैं सर्वाधिक 86 पार्षद सी श्रेणी (70 फीसदी से कम लेकिन 60 फीसद से ज़्यादा या बराबर) में आए हैं। इसी तरह 73 पार्षदों का प्रदर्शन फिसड्डी डी श्रेणी (60 फीसद से कम लेकिन 50 फीसदी से अधिक या बराबर) का रहा है। यह आंकड़े प्रजा फाउंडेशन के उस समेकित रिपोर्ट कार्ड में हैं जो उसने वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक 265 पार्षदों के प्रदर्शन के डेटा के आधार पर तैयार किया है, जिसके मुताबिक तीनों निगमों के केवल नौ पार्षदों का प्रदर्शन 74.33 से 79.98 फसदी के बीच रहा है। इसमें भाजपा के छह, आम आदमी पार्टी के दो तथा कांग्रेस के महज़ एक पार्षद शामिल हैं।

प्रजा फाउंडेशन के संस्थापक और मैनेजिंगिंग ट्रस्टी ने बताया कि राजधानी के पार्षदों का समग्र प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। उत्तरी निगम (एनडीएमसी) के पार्षदों का कुल औसत स्कोर वर्ष 2017-18 के 60.50 फीसदी से गिरकर 2020-21 में 57.92 फीसद हो गया। इसी तरह इस अवधि में दक्षिणी निगम (एसडीएमसी) का 60.48 फसदी गिरकर 56.85 फीसदी तथा पूर्वी नगर निगम (ईडीएमसी) का 61.57 फीसदी से गिरकर 54.40 हो गया।

फाउण्डेशन के निर्देशक ने डेटा के आधार पर बताया कि विभिन्न बैठकों में पार्षदों की उपस्थिति भी धीरे-धीरे कम हो गई है। एनडीएमसी में उपस्थिति वर्ष 2017-18 में 78.81 फीसदी हो गई हैं इसी तरह एसडीएमसी में इस अवधि में 79.62 फीसदी से घटकर 72.37 फीसदी तथा इडीएमसी में 82.34 फीसद से घटकर पार्षदों की मौजूदगी 72.64 प्रतिशत पर आ गई।

चिंताजनक बात यह है कि नागरिकों की शिकायतों की तुलना में मुद्दों को उठाने में पार्षदों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर केवल 38.26 प्रतिशत, वहीं निगमों में उठे कुल 62,184 मुद्दों में आधे से अधिक 32,356 अकेले 69 पार्षदों ने ही उठाए। मतलब जनहित के मुद्दों को उठाने में भी सक्रियता काफी कम पार्षदों की रहीं। कार्यालय में

बाक़ी पेज 11 पर

संपादकीय

शांति मिशन

इस्लामी शिक्षा पर अमल करने में छिपा है उच्च कोटि का राज़

आज पूरा विश्व विभिन्न प्रकार के फिकरी, ज़ेहनी, तबक़ाती, धार्मिक और साम्प्रदायिक अतिवादिता का आमाजगाह बना हुआ है। ऐसी ही कुछ सूरतेहाल अपने प्यारे देश भारत की भी है, जहां बहुमत के घमंड में एक वर्ग अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार पर हर समय डाका डालने का प्रयास करता रहता है जिसने हमारी परम्पराओं और भावनाओं व भाईचारे को समाप्त कर दिया है और शायद यही वजह है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद हमारा प्यारा देश भारत हज़ारों उपलब्धियों के बावजूद अभी भी प्रगतिशील देशों की सूचि से विकसित देशों की सूचि में जगह नहीं बनाया पाया है।

हमारा प्यारा देश भारत और यहां के मुसलमान की हैसियत से प्यारे देश की मुहब्बत हमारा जुजवे ईमान हैं। ज़ाहिर है प्यारे देश भारत में आज जिन मसाएल और मुश्किलात से जूझ रहा है यह एक मुसलमान की हैसियत से हमारे लिए काफी तकलीफदेह हैं। इसके साथ ही यह भी एक हक़ीक़त है कि ख़ुद उम्मते मुस्लिमा भी जिसे कुरआन करीम ने ख़ैरे उम्मत का लक़ब दिया है न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर काफी नीचे और ज़िल्लत का शिकार है जिस पर हर हालत में विचार की आवश्यकता है। जहां तक भारत की बात है हम बार-बार अपने कॉलमों में याद दिला चुके हैं कि उनकी परेशानी का इलाज इस्लाम की शिक्षा पर अमल करके ही हो सकता है। एक नागरिक की हैसियत से वह अपने पड़ोसियों के अधिकार पहचानें और उनके साथ दुखों के बांटने का काम करें। अख़लाके हसना का प्रदर्शन करें और एक दूसरे के दु:ख में शामिल होकर अपनी अच्छी आदतों से उन्हें प्रभावित करें और जहां तक विश्व स्तर पर मुसलमानों के पिछड़ेपन की बात है उसके लिए हमें कुरआन और सुन्नत और ज़मीनी उसूलों को देखना होगा, कुरआन-ए-करीम की एक आयत का खुलासा है कि:-

''तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती है वह तुम्हारे अपने गुनाहों का बदला हैं अल्लाह तआला बहुत से गुनाहों की बातों से दरगुज़र भी कर देता है। (शूरा)

एक दूसरी आयत का खुलासा है कि

''फिर हमने एक को उसके गुनाहों की वजह से सज़ा दी, उनमें से कुछ पर हमने पत्थरों की बारिश की और उनमें से कुछ को हम ने ज़ोरदार सख़्त आवाज़ से दबोच लिया और उनमें से बाज़ को हमने ज़मीन में धंसा दिया और उनमें से बाज़ को हमने पानी में डूबो दिया, अल्लाह ऐसा नहीं है कि उन पर अत्याचार करे बल्कि यह ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। (सूरह अनकबूत)

कुरआन-ए-करीम और इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में देखा जाए तो हमारी ज़िल्लत और पिछड़ने का बुनियादी कारण यह ही दिखेगा कि हम सब इस्लामी शिक्षाओं से दूर हो गए हैं। अहकामाते इस्लाम पर अमल छोड़ चुके हैं और अपनी साख को मज़बूत रखनें और अपनी सुरक्षा के लिए जो खुदाई हुक्म था उससे क़तरा रहे हैं। अल्लाह की ओर से मुसलमानों पर आज़माइशें आती रहती हैं ऐसे समय में अल्लाह की ओर रुजू, सब्र व इस्तिक़ामत और हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।

आज़माइश, मुसीबत और परेशानी के समय एक मुसलमान का इस्लामी इंसानी, अख़्लाक़ी और सामाजिक कर्तव्य यह बनता है कि वह दूसरे मुसलमान की हर मुमकिन मदद करे, हमदर्दी का इज़हार करे। उनकी भरपूर सहायता के लिए प्रभावशाली रणनीति अपनाए। दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों और देशों में मुसलमान जिस अत्याचार और ज़्यादती से त्रस्त हैं, उन पर जो मुसीबतें आ रही हैं उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीडिया और अख़बार से लगभग हर व्यक्ति को उसकी जानकारी है। इन हालात में हर मुसलमान को उनकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए और विश्वभर के मुसलमानों को ऐसे बुरे हालात में इस्लामी शिक्षा यह बताती है कि वह अल्लाह की ओर रुजू करें। व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर कबीरा गुनाहों से तौबा व इस्तग़फार करें। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी बड़ी भयानक और दर्दनाक घटनाएं अक्सर हमारे गुनाहों का नतीजा होते हैं।

यह एक नाकाबिले इंकार हक़ीक़त है कि आपसी लड़ाई झगड़े से हमारी ताक़त बिखर गई है। अपनी बिखरी हुई ताक़त को इकट्ठा करने का एक ही तरीक़ा है कि आपसी झगड़े से अपने को बचाएं। ख़ुद कुरआन-ए-करीम का इरशाद है :- ''और आपसी लड़ाई, झगड़ा न करो वरना डरपोक हो जाओगे, और तुम्हारा रौअब समाप्त हो जाएगा।'' (सूरह अनफाल)

इसलिए आवश्यकता है कि आपसी बिखराव के बजाए आपस में भाई-भाई बनकर ज़िन्दगी बसर करें। कुरआन ने भी सारे मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का भाई क़रार दिया है। सूरह हुजरात की एक आयत का तर्जुमा है कि ''अहले ईमान आपस में भाई-भाई है'' ओर यह बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि मुसीबत के समय एक भाई ही अपने दूसरे भाई की सहायता करता है, हदीस पाक में है :-हज़रत नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल॰ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल॰ ने इरशाद फरमाया ''आपसी मुहब्बत, रहमत और शफक्क़त में तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं जब इंसान के किसी हिस्से में तकलीफ होती है तो उसकी वजह से जिस्म के तमाम भाग बेख्वाबी और बुखार में मुब्तला हो जाता है।

इसलिए हमारे ईमान का तक़ाज़ा है कि हमें विश्व भर में रहने वाले मुसलमानों को पहुंचने वाली तकलीफों का एहसास हों, इस तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना हमारे ईमान की अलामत है। इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए अच्छाई और भलाई की दुआ भी करते रहें इसलिए कि दुआ को मोमिन का हथियार बताया गया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी ए-करीम सल्ल॰ ने फरमाया ''क्या मैं तुम्हें वह अमल बताऊँ जो तुम्हारे दुश्मनों (के जुल्म व सितम) से निजात दे और तुम्हें भरपूर रोज़ी दिलाए, वह कार्य यह है कि अपने अल्लाह से रात दिन दुआ किया करो क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है'' (मुस्नद अबी याली, मुस्नद जाबिर)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल॰ ने फरमाया दुआ उन घटनाओं और मसायल से भी छुटकारा दिलाती है जो नाज़िल हो चुके हैं और उनसे भी जो अभी नाज़िल नहीं हुए इसलिए अल्लाह के बंदों दुआ का एहतमाम करो। (मुस्तदरक हाकिम, किताबुद्दुआ) फिर वह दुआ जो अपने मुसलमान भाई की ग़ैर मौजूदगी में की जाए वह तो जल्द कबूल होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़िं॰ से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल॰ ने फरमाया 'बेशक जल्द क़बूल होने वाली दुआ वह है जो ग़ायब की ग़ायब के लिए हो यानि किसी की ग़ैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ की जाए।'' (सोनने अबी दाऊद)

इसके बाद दूसरा हक़ यह है कि उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूले करीम सल्ल॰ ने फरमाया 'जो व्यक्ति मेरे किसी उम्मती को कोई ज़रूरत इस इरादे से पूरा करे कि वह उम्मती खुश हो जाए तो उस व्यक्ति ने प्रसन्न कर दिया और जिसने मुझे प्रसन्न कर दिया उसने बारी तआला को प्रसन्न कर दिया और अल्लाह पाक को प्रसन्न किया तो अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाख़िल करेंगे।''

ज़िल्लत और पस्ती से निकलने का यह एक नुस्ख़ए कीमिया है जो हमारे लिए कुरआन व हदीस ने तजवीज़ किया है। अब आवश्यकता है उस पर अमल करने और उसे अमली ज़िन्दगी में उतारने की। हालात का तक़ाज़ा भी यही है कि हम सब्र, हिम्मत, हौंसला से हालात का मुक़ाबला करें और अल्लाह के हुज़ूर सज्दा रेज़ होकर अपने गुनाहों से मुआफ़ी चाहें, उसके साथ ही बाहमी झगड़ों और मसाएल से बचें। मज़लूम की मदद करें और अपने भाईयों से ख्वाह वह दीनी हो या वह वतनी भाई हों, हमदर्दी और सहानुभूति का व्यवहार करें और बारगाहे इलाही में उनके लिए हिदायत और ख़ैर व आफियत की दुआ करते रहें। □□

तारीख़े इस्लाम

ख़ुतबाते सीरते तैयिबा

मुफ़्ती मुहम्मद सलमान मंसूरपुरी क़िस्त- 97

पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि : अंसार के लोग गोया कि मेरे जिस्म के अंदर का लगा हुआ कपड़ा हैं, और दुनिया के लोग बाहर के कपड़े हैं''। और आप ने फ़रमाया कि :''अगर हिजरत न होती तो मैं क़बीला अंसार ही का एक फ़र्द होता'' और फ़रमाया कि :''अगर सारी दुनिया किसी रास्ते पर चले और अंसार दूसरे रास्ते पर चलें तो मैं अंसार वाले रास्ते पर चलुंगा''

और अख़ीर में यह फ़रमाया कि:''ऐ अंसार के ज़िम्मेदार लोगो! क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है कि सारी दुनिया तो बैल, बकरियाँ, ऊँटख और सोना चाँदी लेकर जायें और तुम अपने इलाक़े में रसूलुल्लाह को लेकर जाओ'' यह सुनते ही तमाम अंसार सहाबा रो पड़े और बेक़रार हो गए और कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिये, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे लिए सब कुछ हैं। (बुख़ारी शरीफ़, वग़ैरह 2/620)

फिर कुछ अ़रसे के बाद क़बीला बनू हवाज़िन और सक़ीफ़ के लोग पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम की ख़िदमत में आए, और अ़र्ज़ किया कि हमारे माले ग़नीमत को वापस कर दिया जाए, नबी-ए-अकरम अ़लैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मेरा अपना मामला नहीं है, मैंने बहुत से लोगों में माल तक़सीम कर दिया, अब मैं मशवरा करूंगा, बिल आख़िर पैग़म्बर अ़लैहिस्स्लाम के कहने पर यह बात तय हुई कि क़ैदी वापस कर दिए जायें, मगर माल वापस नहीं किया जायेगा। (मुलख़्ख़स: बुख़ारी शरीफ़ 2/618) उन्हीं क़ैदियों में नबी-ए-अकरम अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई बहन शीमा बिन्ते हारिस रज़ि अल्लाहु अ़न्हा भी थीं, पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने उनका बहुत इकराम फ़रमाया और तोह़्फ़े तहाइफ़ देकर उन की क़ौम में वापस किया। फिर उसी के क़रीब औतास और ताइफ़ के ग़ज़वात भी पेश आए, यह सन 8 हिजरी में पेश आने वाले वाक़िआ़त में से हैं।

गज़वा-ए-तबूक

फ़तहे मक्का और ग़ज़वा-ए-हुनैन के बाद इस्लाम की धाक पूरे अ़रब में बैठ चुकी थी, और अब किसी क़बीले में सर उठाने की ताब नहीं थी, लेकिन ये ख़बरें मिल रही थीं कि ईसाइयों की जो सुपर ताक़त है, उन के दिलों में बड़ी कुढ़न पैदा हो रही है।

चुनान्चे पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम को यह ख़बर मिली कि रूमी बादशाह मनीदा मुनव्वरा पर चढ़ाई करने के लिए ग़स्सान के इलाक़े में फ़ौज जमा कर रहा है, यह सन 9 हिजरी का वाक़िआ़ है, सख़्त गरमी का ज़माना था, मदीना मुनव्वरा की पूरी तिजारत खजूर और उसकी फ़रोख़्तगी (बेचना) पर मुनहसिर थी, बाग़ात फ़लों से लदे पड़े थे, खजूर पक गई थीं, पैग़म्बर अ़लैहिस्सलाम ने ऐलान फ़रमाया कि फ़लाँ दुश्मन से मुक़ाबले की तैयारी करनी है, और सब को चलना है। (जारी)

पाकिस्तान नहीं सुधरा तो तबाह हो जाएगा

इश्तियाक अहमद

इश्तियाक अहमद पाकिस्तानी मूल के मशहूर लेखक हैं। वह स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी हैं। पॉलिटिकल इस्लाम, एथनिसिटी एंड नैशनलिज़्म, ह्यूमन, माइनारिटी एंड राइट्स, पार्टीशन स्टडीज आदि विषयों पर इनके शोध हैं। 'जिन्ना : उनकी सफलताएं, असफलताएं ओर इतिहास में उनकी भूमिका, द पंजाब ब्लडेड, द 1947 ट्रेजडी थ्रू सीक्रेट ब्रिटिश रिपोर्टर्स एंड फसर्ट पर्सन एकाउंट्स जैसी दर्जनों चर्चित पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। यहां पेश हैं इश्तियाक अहमद से हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश।

प्रश्नः- दोनों देशों को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान अपने देश में आयोजन कर रहा है भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आप इन गुज़रे 75 सालों में जश्न लायक़ क्या बदलाव देखते हैं?

उत्तरः- जश्न लायक़ तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब मुल्क आज़ाद होते हैं, तो अपने ढंग से सेलिब्रेट करते हैं जैसे-भारत, 'अमृत महोत्सव' मना रहा है। दोनों देश खुशी मना रहे हैं यानि अपनी मौजूदगी का एहसास कर रहे हैं। दोनों देशों में विभिन्न तरह की परेशानियां और गुरबत है, पर इन 74 सालों में बहुत तरक्क़ी भी हुई है। भारत एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी। पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश था, उसमें भी बहुत बदलाव आए हैं लेकिन इन 74 सालों में दोनों देशों के बुनियादी ढांचे में आज भी असमानता, वर्ग और वर्ण व्यवस्था की मौजूदगी बरकरार दिखती है। दोनों ओर के अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा होती है।

प्रश्नः- तालिबान अफ़ग़ानिस्तान में वापस आ गया है। क्या इस इलाक़े में हमेशा से इसी तरह की उथल-पुथल रही है, या कभी इसका कोई लंबा इलाज हुआ हो?

उत्तरः- वर्ष 1973-1979 तक अफग़ानिस्तान में इस तरह के हालात नहीं थे, जैसे आज हुए हैं। वहां जब बादशाह ज़हीर शाह की हुकूमत थी, तब देश शांति, भाईचारा, महिलाओं को पूर्ण आजादी मिली हुई थी। फिर वहां रशियन आ गए और पाकिस्तान तथाकथित अफग़ानिस्तान जिहाद के नाम पर उसमें शामिल हो गया। तालिबान तो वहां 1994 में आया, जो अपने आपको इस्लामिक स्टूडेंट मानते थे और वर्ष 1996 में सत्ता हथिया ली थी। वर्ष 2021 में ये तालिबानी पाकिस्तान सहित समूची दुनिया के लिए मुसीबत बन गए हैं।

प्रश्नः- अफग़ानिस्तान, तालिबान और उस ओर के इलाक़ों को ज़ेरे नज़र रखते हुए बताईए कि पाकिस्तान कैसे आज इस मोड़ पर पहुंच गया?

उत्तरः- पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पर अगर सब कुछ करेगा तो अपने देश की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह मटियामेट कर देगा। अब पड़ोस में तालिबानी सत्ता में आ चुके हैं, उसे कैसे नियंत्रित करना है? यह उसके लिए मुख्य मुद्दा होना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान अब वह काम नहीं कर सकता, जो उसने सालों तक किया है। उन्हें तालिबान को नियंत्रित करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान को चाहिए कि वह कोशिश करे तालिबान अफग़ानिस्तान के बाहर न निकले।

प्रश्नः- पाकिस्तान में यह बात क्यों नहीं उठती कि उसे एक मुस्लिम राष्ट्र न होकर लोकतांत्रिक देश होना चाहिए?

उत्तरः- पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने डबल स्टेंडर्ड के लिए बदनाम है। बाकी दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के साथ तकलीफ होती है तो यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं इनका कोई नैतिक मूल्य एक जैसा नहीं है। आज़ादी के बाद भारत ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने का फैसला किया। पाकिस्तान वैसा ध र्मनिर्पेक्ष राष्ट्र नहीं बना पाया। यह पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्य है। दोनों में यह बहुत बड़ा फर्क है।

प्रश्नः- अगर तालिबानी इस्लाम के अनुसार देश चलाना चाहते हैं तो ग़लत क्या है.?

उत्तरः- गलत कुछ नहीं है, लेकिन इस्लाम के अनुसार सही से चलाकर तो दिखाएं, जहां शांति हो, देश में तरक्क़ी हो, लोगों को न्याय मिले, महिलाओं को सभी तरह के अधि कार मिलें। तब किसी को कुछ एतराज़ नहीं होगा। लेकिन इस्लाम के नाम पर अल्पसंख्यकों, ग़ैर मुसलमानों के साथ अमानवीय अत्याचार करना, औरतों के अधिकारों को छीन लेना। आज कोई मुल्क तालिबान जैसा नहीं चल सकता है।

प्रश्नः- क्या पाकिस्तान में शादी-ब्याह में जाति बिरादरी देखी जाती है?

उत्तरः- हमारे यहां भी बिरादरियों के अंदर ही शादियां होती हैं यहां (पाकिस्तान) जो लोग भूमिहीन हैं, उन्हें लोग नीचा समझते हैं, लेकिन भारत में जो जाति और वर्ण व्यवस्था है, वह बहुत मज़बूत है।

प्रश्नः- भारत के मुसलमान लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इस्लामिक राष्ट्रों में लोकतंत्र की बात नहीं होती, ऐसा क्यों..?

उत्तरः- यह मुसलमानों की बहुत बड़ी समस्या है, जब मुस्लिम अल्पसंख्यक होते हैं, तब लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन जब बहुसंख्यक होते हैं तो इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं।

प्रश्नः- इस्लामिक जिहाद के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं?

उत्तरः- शासकों ने जिहाद के हवाले से बहुत जंगें लड़ी हैं। उसका एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। इस्लाम सऊदी अरब से पूरी दुनिया में फैला। लेकिन इसका मार्ग दर्शन भी हैं अब कोई यह कहे कि हम जिहाद करेंगे, दूसरे को हरा देंगे तो यह आज के दौर में संभव नहीं है। जिहाद के नाम पर कोई मुस्लिम देश अब जंग नहीं जीत सकता। समझना चाहिए कि जिहाद की समय सीमा अब खत्म हो गई है।

प्रश्नः- इस्लाम एक दर्शन भी तो है इस पर आपकी क्या राय है?

उत्तरः- इस्लाम की राजनीतिक विचारधारा का विश्लेषण बाकी विचारधाराओं की ही तरह करना पड़ेगा। ❑❑

यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी एसपी है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी उसी का होगा : इमरान मसूद

प्रश्नः- आप खुद भी यूपी से हैं, राज्य की सियासी नब्ज़ पर पकड. रखते हैं, वहां का क्या राजनीतिक परिदृश्य देख रहे हैं.?

उत्तरः- यूपी में भाजपा की जो सरकार है, उसने पांच साल के दौरान एक भी ऐसा काम नहीं किया, जिसके द्वारा वह जनता का वोट लेने का अधिकार जता सके। इतने बड़े बहुमत वाली सरकार के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा नाराजगी पहले कभी नहीं देखी गई, लेकिन उसके हक़ में जो एक बात जा रही है, वह यह है कि विपक्ष खेमों में बंटा हुआ है। वोटों का विभाजन भाजपा की ताक़त बना हुआ है और अगर वोटों का विभाजन नहीं रुका तो भाजपा को वापस आने से नहीं रोक सकते।

प्रश्नः- उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आख़िरी सरकार 89 तक थी, उसके बाद करीब तीन दशक बीत गए, राज्य में उसकी वापसी नहीं हो सकी, इसकी क्या वजह है.?

उत्तरः- वक़्त के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो यही हश्र होगा। जिस वक़्त की आप बात कर रहे हैं, उस दौरान यूपी की राजनीति का चेहरा, उसका मिजाज़ सब कुछ बदल गया। कास्ट राजनीति हावी हो गई। कांग्रेस वह नहीं कर सकी। हम सबको अपना बनाने के चक्कर में किसी के भी नहीं हो सके।

प्रश्नः- 2017 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, इसे मील का पत्थर माना जा रहा था, लेकिन गठबंधन फेल हो गया, क्यों?

उत्तरः- यह गठबंधन कोई जादू की छड़ी नहीं था। सफलता के लिए वक्त चाहिए था। दोनों पार्टियों के जो वोटर हैं, उनका यकीन पुख़्ता होना ज़रूरी था कि हम एक हैं और एक रहेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा मज़बूत होना चाहिए था। यह तभी होता, जब गठबंधन लंबा चलता, लेकिन गठबंधन चुनाव से ठीक पहले हुआ और नतीजा निकलते ही ख़त्म हो गया। कम से कम मुझे फौरी तौर पर कोई उलटफेर की उम्मी उस वक्त कम नहीं थी।

प्रश्नः- इस बार तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ गठबंध न करने से मना कर दिया है, बीएसपी ने भी अपने दरवाज़े बंद कर रखे हैं, यूपी में कांग्रेस के लिए क्या रास्ता बचता है?

उत्तरः- समाजवादी पार्टी यूपी में भाजपा के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी होने के नाते उसकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी है। उसे समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों को गोलबंद करना चाहिए।

मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है या इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला है। प्रियंका गांधी कांग्रेस का राष्ट्रीय चेहरा है, उन्हें यूपी का चेहरा बनाना उन्हें सीमित करना हो गया। अभी बात तो कांग्रेस के सवाईवल की है। पहले कांग्रेस को सर्वाइव तो करने दीजिए फिर मुख्यमंत्री का चेहरा तय होता रहेगा।

प्रश्नः- क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर यूपी के चुनाव मैदान में उतर सकती है? अगर ऐसा होता है तो क्या वहां बाज़ी पलटेगी?

उत्तरः- मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है या इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला है। प्रियंका गांधी कांग्रेस का राष्ट्रीय चेहरा है, उन्हें यूपी का चेहरा बनाना उन्हें सीमित करना हो गया। अभी बात तो कांग्रेस के सवाईवल की है। पहले कांग्रेस को सर्वाइव तो करने दीजिए फिर मुख्यमंत्री का चेहरा तय होता रहेगा।

प्रश्नः- अगर कांग्रेस और एसपी का गठबंधन हो जाता है तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? क्या कांग्रेस अखिलेश यादव को सीएम पद का उम्मीदवार स्वीकार कर लेगी?

उत्तरः- इस मुद्दे पर पार्टी की सामूहिक तौर पर या अन्य नेताओं की क्या राय है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि राजनीति नंबरों का खेल है। आज की तारीख़ में यूपी में भाजपा के ख़िलाफ़ विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ही है तो स्वाभाविक रूप से सीएम का चेहरा भी उसी का होगा। कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष की अन्य पार्टियों को भी उस चेहरे को स्वीकार करना होगा।

प्रश्नः- तो क्या आप ऐसे किसी गठबंधन के लिए कोई पहल करेंगे?

उत्तरः- मैं तो सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि अगर यूपी में भाजपा को हराना है तो एक मज़बत विकल्प तैयार करना ही होगा।

प्रश्नः- सुनने को तो यह मिला है कि आप अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, देर सबेर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं

उत्तरः- संपर्क में होने की जो बात आप कह रहे हैं कि तो वह संपर्क इतना है कि मेरी उनकी मुलाक़ात अभी पिछले दिनों पूर्व राज्यपाल अजीज़ कुरैशी के यहां विवाह समारोह में हुई थी, जिसमें उनके साथ कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई ही नहीं।

प्रश्नः- यूपी में मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद कौन होगा, एसपी/बीएसपी/या कांग्रेस?

उत्तरः- मुस्लिम वोटर्स की ही बात क्या कर रहे हैं, मैं तो सभी जाति और धर्म के वोटरों की बात कर रहा हूं। भाजपा के ख़िलाफ़ जो भी मज़बूत विकल्प बनता दिखेगा वोटर्स की पहली पसंद वही होगा। ❑❑

पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा

उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति को सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले जस्टिस नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी सम्बद्ध पक्षों की दलीलें सुनीं। केन्द्र ने अपना रुख़ स्पष्ट कर दिया है। अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपालन ने कहा है कि आजादी के करीब 75 साल बाद भी एससी, एसटी के लोगों को उस स्तर पर नहीं लाया जा सका है, जहां अगड़ी जातियों के लोग हैं। एससी, एसटी वर्ग के लोगों को ग्रुप-ए श्रेणी के उच्च पद प्राप्त करना मुश्किल है। अब समय आ गया है कि जब शीर्ष कोर्ट को एससी/एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए ठोस आधार देना चाहिए।

पदोन्नति में आरक्षण का मसला काफी जटिल और विवादास्पद रहा है। आरक्षण को लेकर सबसे पहले 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में एसीसी/एसटी समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए इसे 5 साल के लिए लागू रखने का आदेश दिया था। इन्दिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी यह मामला विवादों में है हालांकि वर्ष 1995 में संसद ने 77वें संविधान संशोधन पारित करके पदोन्नति में आरक्षण जारी रखा था। इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है लेकिन यह मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। तब न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि इस संदर्भ में आरक्षण दिया जा सकता है लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी। इसके बाद 85वां संविधान संशोधन पारित किया गया और इसके माध्यम से परिणामी वरिष्ठता की व्यवस्था की गई। पदोन्नति में एससी/एसटी की तत्कालीन स्थिति नागराज और अन्य बनाम भारत सरकार वाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 के निर्णय के पश्चात् पुन: बदल दी गई। नागराज और अन्य बनाम भारत सरकार संसद द्वारा किए गए 77वें और 85वें संशोधनों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई। न्यायालय ने अपने निर्णय में इन संवैधानिक संशोधनों को तो सही ठहराया किन्तु पदोन्नति में आरक्षण के लिए तीन मापदंड निर्धारित किए। इन तीन मापदंडों में पहला एससी/एसटी और समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, दूसरा सार्वजनिक पदों पर एससी/एसटी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होना और तीसरा इस प्रकार की आरक्षण नीति का प्रशासन की समग्र दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पदोन्नति में आरक्षण के विरोधियों और आलोचकों का मानना है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक स्तर पर सभी लोगों से समान व्यवहार करना है किन्तु पदोन्नति में इसे लागू करने से यह विपरीत कार्य करता है और पहले से समान स्तर पर मौजूद लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करता है। रोज़गार और पद प्राप्त करना सामाजिक भेदभाव की समाप्ति सुनिश्चित नहीं करता है। अत: पिछड़ेपन के आंकलन के लिए एकमात्र साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आलोचकों का यह भी मानना है कि सार्वजनिक पदों पर आरक्षण देने से यह प्रशासन की दक्षता में कमी ला सकता है। पदोन्नति में आरक्षण के समर्थक आरक्षण को एक प्रकार से सकारात्मक भेदभाव के रूप में देखते हैं। वे आरक्षण को सामाजिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान करना मानते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि वह एससी/एसटी को आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर के मुद्दे पर विचार नहीं कर रही, वह सिर्फ इस बात पर विचार कर रही है कि क्या पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए उच्च पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए संख्यात्मक आंकड़ा लाना जरूरी है? और या यह आरक्षण देने से प्रशासनिक दक्षता तो प्रभावित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार और कई राज्यों की याचिकाओं पर भी विचार कर रही है, जिन्होंने पदोन्नति में आरक्षण देने के अनुमति मांगी है केन्द्र सरकार ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4ए) के तहत आरक्षित वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में केन्द्र सरकार से उन क़दमों की जानकारी मांगी थी जो केन्द्रीय नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकलन करने के लिए उठाए गए हैं। पीठ ने सरकार से कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए वर्ष 2006 के नागराज मामले में संविधान पीठ के फैसले का पालन करने के लिए की गई कवायद की जानकारी उपलब्ध करवाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ अब इस बात का फैसला करेगी कि नागराज मामले में दिए गए फैसले के अनुसार एक समुचित अनुपात या प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का आधार होना चाहिए।

यदि हम आरक्षण की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए जनसंख्या से जाते हैं, तो इसकी बड़ी ख़ामियां हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक होगा। इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि सबको समान अवसर मिलें। ❑❑

अनावश्यक विवादों में मीनाक्षी लेखी

विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी विवादों में आ गई हैं। उन्हें गुयाना के राजदूत द्वारा दीवाली पार्टी में आमंत्रित किया गया था जिसमें वह भाग लेनी पहुंची थीं। पार्टी में उपस्थिति राजनयिकों को दिवाली का अर्थ समझाते हुए, उन्होंने उन्हें अपनी मुट्ठी हवा में लहराते हुए जय श्री राम का जयकारा लगाने को कहा, वहां उपस्थित कुछ राजनयिकों को इसका अर्थ समझ नहीं आया और उन्होंने मीनाक्षी लेखी के साथ नारा लगाया। लेकिन दूसरे देशों, विशेष मुस्लिम देशों के राजनयिक इस बात से काफी नाराज़ हुए कि किसी सामाजिक कार्यक्रम में धार्मिक/राजनीतिक नारे का इस्तेमाल किया गया था। शायद इसे लेकर विदेश मंत्रालय के पास एक अनौपचारिक शिकायत दर्ज की गई है। इसके बाद ही सरकार ने लेखी के सहयोगी, विदेश कार्यालय में दूसरी कनिष्ठ मंत्री वी. मुरलीधरन को गुयाना के दौरे के लिये प्रतिनियुक्त किया। पहले मीनाक्षी लेखी को इस दौरे पर जाना था। यह पहली बार नहीं है जब लेखी ने राजनीयिक समुदाय में ऐसी उपस्थिति दर्ज की। हाल ही में, उन्होंने एक करवाचौथ पार्टी की मेज़बानी की, जहां उन्होंने राजनयिक पत्नियों को पारंपरिक पूजा करने को कहा और यहां तक कि पति के चेहरे को देखने के लिए चलनी वाली छलनी भी उनको दी गई। जबकि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना बहुत अच्छा है, पर अनेक राजनयिक समुदाय हिन्दू रीति रिवाज़ों के इस अनावश्यक आक्रामक प्रचार से नाखुश दिख रहा है।

माउंटेनियरिंग युवाओं के लिए रोमांचक रोज़गार

जीवन की उत्पत्ति से लेकर अब तक न जाने कितने रहस्य मनुष्य द्वारा बेशक सुलझाए जा चुके हों, लेकिन फिर भी प्रकृति हमारे लिए अजेय ही बनी रहेगी। यह जानते हुए भी मनुष्य लगातार कुदरत के करिश्मों को खंगालने में लगा हुआ है। इन्हीं में से एक जुनून है, माउंटेनियरिंग अर्थात् पर्वतारोहण का। आज हॉबी के साथ साथ माउंटेनियरिंग युवाओं के लिए रोज़गार का आधार भी बन चुका है। यह क्षेत्र साहसी और जोखिम से खेलने वाले युवक और युवतियों को बहुत आकर्षित करता है। माउंटेनियरिंग अनुशासन की कला सिखाता है क्योंकि आत्मविश्वास और अनुशासन के बग़ैर माउंटेनियरिंग को कई स्थितियों में त्वरित निर्णय लेना पड़ता है। अर्थात् तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, दृढ़ निश्चयी होना तथा ख़तरों से खेलने का शौक होना इस क्षेत्र में सफल होने की कुछ प्रमुख शर्तें हैं। माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रकृति से लगाव होना भी बहुत ज़रूरी है। जो युवा इस तरह की कठिनाईयों और समस्याओं से जूझने का माद्दा रखते हैं, उन्हें माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहिए। माउंटेनियरिंग का दुनियाभर में एक रोमांचक खेल के रूप में देखा जाता है। हालांकि चाहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो या फिर भी माउंटेनियर (पर्वतारोही) इन पर चढ़ाई नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी से लेकर बछेंद्री पाल, कामी राती शेरपा आदि तक बहुत से जांबाज युवक युवतियां इस क्षेत्र में अपना मुकाम बना चुके हैं।

माउंटेनियरिंग की प्रमुख गतिविधियों पर एक नज़र

क्लाइंबिग:- पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की प्रकृति आदि को ध्यान में रखकर पहाड़ की चढ़ाई करना, क्लाइंबिंग कहलाता है।

कैंपिंग:- पहाड़ पर चढ़ाई करने के दौरान कैंप लगाकर कई दिनों तक पहाड़ पर सीमित संसाधनों के साथ रहना और वहां की जलवायु के अनुसार खुद को ढालना या व्यवस्थित करना कैंपिंग एक्टिविटी में शामिल है।

स्नो ट्रैकिंग:- किसी बर्फ से ढंके पहाड़ जैसे माउंट एवरेस्ट पर तापमान और वातावरण संबंधी बाधाओं को पार करते हुए उस पर चढ़ाई करना, स्नो ट्रेकिंग कहलाता है।

हाइकिंग:- लंबी दूरी के लिए तेज गति से किसी पहाड़ की चढ़ाई करने को हाइकिंग कहा जाता है। हाइकिंग स्वास्थ्य संबंधी फायदों और एक्सरसाइज के उद्देश्य से की जाती है। यकीनन माउंटेनियरिंग में कैरियर बनाने के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। माउंटेनियरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति न केवल सफल पर्वतारोही बन सकता है, बल्कि भूकंप जैसी आपदाओं के साथ भी लोगों की जान बचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। माउंटेनियरिंग से संबंधित कई प्रकार के जॉब ओरिएंटेड कोर्स अस्तित्व में आ चुके हैं। माउंटेनियरिंग में बैचलर डिग्री कोर्स तीन सालों में पूरा किया जा सकता है। इसमें प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा किसी भी विषय समूह से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा तथा प्रोफेशनल पाठयक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना आवश्यक है। तीन एवं छह माह के सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए दसवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा भी सर्च एवं रेस्क्यू कोर्स, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन आदि कोर्स की भारी मांग है।

माउंटेनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े कुछ अन्य रोज़गार

क्लाइंबिंग गाइड:- क्लाइबिंग गाइड पर्वतारोहियों को पहाड़ों की सटीक जानकारी देते हैं। इसके लिए उनके पास मौसम की स्थिति और पहाड़ों के विभिन्न रास्तों के बारे में पता होता है, ताकि लैंडस्लाइड या

बाक़ी पेज 11 पर

इस्लामी दुनिया

पाक के चीफ जस्टिस ने किया पुनर्निर्मित हिन्दू मंदिर का उद्घाटन

पेशावर : पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) गुलज़ार अहमद ने ख़ैबर पखतूनख्वा (केपी) के करक जिले में पुनर्निर्मित श्री परमहंस महाराज मंदिर का दिवाली पर उद्घाटन किया। पिछले वर्ष दिसंबर में कुछ अराजक तत्वों ने मंदिर को तोड़ कर ध्वस्त कर दिया था। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए सीजे गुलजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए क़दम उठाए हैं और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में उग्र भीड़ द्वारा मंदिर तोड़े जाने ओर आग लगा देन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्माण का आदेश दिया था।

बांग्लादेश : पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिन्हा को 11 साल की क़ैद

ढाका : बांग्लादेश की एक अदालत ने देश के पूर्व शीर्ष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा को भ्रष्टाचार के दो मामलों में 11 साल के जेल की सज़ा सुनाई है। देश में अल्पसंख्यक समुदाय के पहले मुख्य न्यायाधीश पर लॉन्ड्रिंग और विश्वास भंग करने संबंधी दो मामलों में यह सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में सिन्हा को धनशोधन का मुख्य लाभार्थी बताया। 70 वर्षीय सिन्हा किसान बैंक पर चार करोड़ रुपये के शोधन से जुड़े एक मामले में 11 वर्ष की सज़ा गई थी।

नाइजर स्कूल में आग लगने से 20 बच्चों की मौत

नियामी : नाइजर के दूसरे सबसे बड़े शहर मरादी के एक स्कूल में आग लगने के कारण 20 से ज़्यादा बच्चों क मौत हो गई और दर्जनों ज़ख़्मी हो गए। एएफएन नामक स्कूल में फूस से बनी तीन कक्षाएं आग की चपेट में आई जिससे तीन से आठ साल की आयु के बच्चों की जान चली गई। बता दें कि पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में छात्रा के लिए स्कूलों में अस्थायी क्लासरूम फूस के बनाए जाते हैं।

पाकिस्तान की ताक़त बढ़ाने की चीन की चाल

चीन ने 2017 में पाकिस्तान के साथ हुई डील के बाद अब एक नौसेना को टाइप-045 स्टील्थ युद्धपोत सौंपकर नया पैंतरा चला है। चीन अरब सागर में भारत की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिशों के तहत यह क़दम उठा रहा है। इस आपूर्ति पर चीनी सरकारी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये युद्धपोत किसी भी रडार को चकमा देने और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाईलों व अत्याधुनिक तोपों से लैस है। चीन ने एक कमीशन सेरेमनी के दौरान पाक को पहला युद्धपोत सौंपा, चीन को ऐसे चार युद्धपोत बनाने हैं। यह जमीन से जमीन, जमीन से हवा, समुद्र के अंदर और सर्विलांस की खूबियों से लैस हैं।

क़ुदरत का क़हर और सबक़

अतुल कनक

जाते मानसून ने इस बार केरल और उत्तराखंड सहित कई जगह जिस तरह का रौद्र रूप दिखाया, उसने सामान्य जन को भी यह सोचने पर विवश कर दिया है कि यह प्रकृति का प्रगल्भ प्रकोप मात्र था या प्रलय की संभावनाओं की आहट? उत्तराखंड और केरल भौगोलिक दृष्टि से भारत भूमि की दो विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। यदि परस्पर इतनी दूर स्थित दो राज्यों में बारिश अफरा-तफरी मचाती है, वह भी आधा अक्तूबर बीत जाने के बाद, तो यह सोचने पर विवश होना ही पड़ेगा कि कहीं जलवायु में ऐसे परिवर्तन तो नहीं हो रहे जो आने वाले समय में सामान्यजन के लिए इससे भी अधिक कठिन हालात उत्पन्न कर दें? यह आशंका इसलिए भी बलवती होने लगी है क्योंकि आंकड़ों की दृष्टि से पूरे मौसम में जितनी बारिश हुई है, उसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए असहज या अपूर्व नहीं कहा जा सकता।

आंकड़ों के अनुसार बारिश अधिक नहीं हो रही है। यों भी मौसम में अच्छी या अधिक बारिश होने को असामान्य नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वातावरण में बढ़ी हुई आर्द्रता कई बार अतिवृष्टि जैसी स्थिति क़ायम कर देती है। इस तथ्य को समझने के लिए हमें यह बात समझनी होगी कि पिछले एक सौ तीस सालों में धरती का ओसत तापमान करीब 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इतना तापमान बढ़ने के कारण जब धरती की सतह पर मौजूद जल स्रोतों से वाष्पीकरण होता है तो वातावरण में नौ से दस प्रतिशत तक आर्द्रता यानि नमी बढ़ जाती हैं यह नमी हवाओं में टिकी रहती है।

जलवायु अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि आंकड़ों के अनुसार बारिश अधिक नहीं हो रही है। यों भी मौसम में अच्छी या अधिक बारिश होने को असामान्य नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वातावरण में बढ़ी हुई आर्द्रता कई बार अतिवृष्टि जैसी स्थिति क़ायम कर देती है। इस तथ्य को समझने के लिए हमें यह बात समझनी होगी कि पिछले एक सौ तीस सालों में धरती का ओसत तापमान करीब 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इतना तापमान बढ़ने के कारण जब धरती की सतह पर मौजूद जल स्रोतों से वाष्पीकरण होता है तो वातावरण में नौ से दस प्रतिशत तक आर्द्रता यानि नमी बढ़ जाती हैं यह नमी हवाओं में टिकी रहती है। जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो हवा उस नमी को धारण किए रहती है और बारिश प्रारंभ होने पर संपूर्ण संचित नमी को कुछ ही क्षणों में छोड़ देती है। यही कारण है कि उक्त दिनों बादल फटने जैसी स्थितियां बार-बार बनी। कुदरत का यह क़हर क्यों टूटा।

पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण हवा में नमी बढ़ने के मूल में कार्बन उत्सर्जन है। सारी दुनिया अब कॉर्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सकारात्मक योजनाएं लागू करने पर बल दे रही हैं। लेकिन कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण पाना इतना आसान भी नहीं है। बिजली के उपभोग से लेकर परिवहन तक में मनुष्य प्रकृति के आंलच में अनियंत्रित कार्बन छोड़ रहा है और यह कार्बन उत्सर्जन दुनिया भर में जलवायु संकट का कारण बन रहा है। क्या कोई आसानी से इस तथ्य पर विश्वास कर सकेगा कि जब हम ऑनलाइन किसी गाने को सुनते हैं, तब भी वातावरण को अवांछित कार्बन उत्सर्जन सौंप देते हैं। इंटरनेट से अपने फोन पर जिस फाइल को डाउनलोड किया जाता है या सीधा लिया जाता है तो वह फाइल किसी सर्वर में सुरक्षित रहती है। सर्वर को ठंडा करने के लिए और उसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और अनियंत्रित विद्युत उपभोग भी तो दुनिया में उस कार्बन उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार है, जिसके कारण दुनियाभर के वैज्ञानिक और पर्यावरणविद चिंतित हो रहे हैं।

पिछले दिनों केरल और उसके तुरंत बाद उत्तराखंड में जो बारिश हुई, उसमें भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं ने आबादी के एक बड़े हिस्से को अस्त-व्यस्त कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ही पिछले कुछ सालों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ॰ राक्सी मैथ्यू ने एक जगह कहा भी है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए शहरी और ग्रामीण विकास नीति को अलग-अलग करना होगा। पहले भी वैज्ञानिक इस बात पर ज़ोर देते आए हैं कि भारत में भूमि उपयोग की नीतियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। हमें ऐसी नीतियों को अपनाना होगा जो जलवायु परिवर्तन की अनियमितताओं का सामना कर सकें।

दरअसल, पिछले कुछ सालों में भारत के विभिन्न शहरों में आई बाढ़ों की स्थिति का आंकलन किया जाए तो यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आएगा कि आसमान से बरसते समय पानी ने उतना तांडव नहीं किया, जितना रौद्र रूप बस्तियों या सड़कों पर पानी जमा होने के कारण देखने को आया। कारण स्पष्ट है। हमने अपने विकास को जिस तरह नियोजित किया कि बारिश के पानी की निकासी के परंपरागत मार्ग तक बंद कर दिए। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा शहर के उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। कोटा शहर उस हाड़ौती के पठार के सबसे निचले हिस्से में बसा है, जो हाड़ौती का पठार काल के किसी खंड में प्रसिद्ध गोंडवाना पठार का हिस्सा रहा था। स्वाभाविक तौर पर पठार के ऊपरी हिस्से में बरसने वाला पानी तेज़ी से नीचे की ओर आता था। इसे देखते हुए सन 1346 ईस्वी में बूंदी के राजकुमार धीरदेह ने इस पठार के विभिन्न हिस्सों में तेरह तालाब इस तरह बनवाए कि बस्तियों की ओर बहते पानी को अपने विस्तार में सहेज सकें। लेकिन आज़ादी के बाद विकास के नाम पर ये तालाब अतिक्रमण के शिकार होते चले गए और वहां बाजार, बस्तियां बसती चली गईं। इससे बरसात के पानी के प्रवाह अवरुद्ध हो गया तो पानी ने बस्तियों में तांडव मचाना शुरू कर दिया। यही सब पहाड़ी इलाकों में हुआ। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं के बाद जो जल प्रलय देखने को मिलने लगा है, उसके मूल में भी पहाड़ों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण है। केरल में बह जाने और तटीय ज़मीन धंसने की घटनाएं भी इसीलिए हो रही हैं कि हम प्राकृतिक स्रोतों का रास्ता रोकने लगे हैं।

जलवायु पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का मानना है कि केरल या उत्तराखंड जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के किसी भी हिस्से को त्रस्त कर सकती हैं, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और अनियंत्रित तरीके से ज़मीनों को अतिक्रमित करने की प्रवृत्ति आम है इसलिए नीति नियंताओं को सजगता और दूरदृष्टि के साथ ऐसी योजनाएं लानी होंगी जिनके कारण पानी के प्रवाह का मार्ग अवरुद्ध न हो और बरसात में एकत्र हुआ पानी सहजता से निकास पा सके। जलवायु परिवर्तन के कारण उपस्थित होने वाली आपात स्थितियों से बचने के लिए हमें उन स्थितियों पर भी नियंत्रण स्थापित करना होगा जो अवांछित जलवायु परिवर्तन की कारक हैं। कार्बन उत्सर्जन उनमें प्रमुख हैं। पेरिस समझौते का सहभागी होने के कारण भारत को यों भी अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य होने तक की स्थिति पर लाना है। यह उल्लेखनीय है कि दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद कॉर्बन उत्सर्जन की दृष्टि से भारत तीसरे नंबर पर है। कहा जा सकता है कि केरल या उत्तराखंड की घटनाओं के बहाने प्रकृति ने हमें आगाह किया है कि हम पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील हों और जलवायु परिवर्तन के प्रति सजग। ❑❑

जलवायु पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का मानना है कि केरल या उत्तराखंड जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के किसी भी हिस्से को त्रस्त कर सकती हैं, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को जहां जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और अनियंत्रित तरीके से ज़मीनों को अतिक्रमित करने की प्रवृत्ति आम है इसलिए नीति नियंताओं को सजगता और दूरदृष्टि के साथ ऐसी योजनाएं लानी होंगी जिनके कारण पानी के प्रवाह का मार्ग अवरुद्ध न हो और बरसात में एकत्र हुआ पानी सहजता से निकास पा सके।

कैसे मिले भुखमरी से मुक्ति

रिज़वान अंसारी

हाल में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति ख़राब बताई गई है। एक सौ सोलह देशों की सूचि में पहले सौ में भारत को जगह नहीं मिलना स्थिति की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत इस बार 101वें स्थान पर रहा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान (92), बांग्लादेश (76) और म्यांमा (71) से भी पीछे है। रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को 'गंभीर' बताया गया है। हालांकि तथ्यों पर ग़ौर करें तो 2020 में भारत 94वें स्थान पर था, अब सात पायदान और नीचे खिसक गया है। ज़ाहिर है, भुखमरी से निपटने में हमारे प्रयासों में खामियां हैं और हम इस दिशा में वैसे क़दम नहीं उठा रहे है जो बेहद आवश्यक है। ग़ौर करने वाली बात यह है कि 2020 की सूचि में कुल देश एक सौ सात थे। इस हिसाब से पिछले वर्ष भारत से ख़राब प्रदर्शन करने वाले देशों की तादाद 13 थी, जबकि इस बार 15 है यानि भारत को दो पायदान का फायदा ही हुआ है लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि 2020 में 93वें देश हमसे बेहतर थी, जबकि इस बार सौ देश हमसे बेहतर कर पाए।

इस सूचकांक में भूख की स्थिति के आधार पर देशों को शून्य से सौ अंक दिए गए हैं। दस से कम अंक का मतलब है कि देश में भूख की समस्या बेहद कम है। इसी तरह 20 से 34.9 अंक का मतलब भूख का गंभीर संकट और 35 से 49.9 अंक का मतलब है कि हालात चुनौतीपूर्ण हैं। इस बार भारत को 27.5 अंक मिले हैं यानि संकट गंभीर है। अब प्रश्न है कि आख़िर ऐसी स्थिति क्यों है? दरअसल, यह सूचकांक चार पैमानों पर तैयार किया जाता है। ये हैं – अल्पपोषण, लंबाई के हिसाब से कम वज़न वाले बच्चे, उम्र के मुताबिक कम लंबाई वाले बच्चे और बाल मृत्यु दर (पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर)। रिपोर्ट की मानें तो भारत में 17.3 फीसदी बच्चे लंबाई के अनुपात में कम वजन की समस्या से जूझ रहे हैं और यह आंकड़ा दुनिया के सभी देशों में अधिकतम है। वहीं, 34.7 फीसद बच्चे बौनेपन के शिकार हैं। हालांकि बाल मृत्यु दर में भारत की स्थिति अच्छी बताई गई है लेकिन पोषण के स्तर पर भारत की ख़ासी आलोचना हुई है।

अगर भुखमरी सूचकांक से इतर सी बात करें तो भारत की स्थिति कोई बेहतर नहीं आंकी जा रही है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020 के दावों पर यक़ीन करें तो भारत दुनिया के उन 88 देशों में शामिल है जो अगले चार वर्ष यानि 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को हासिल करने में सफल नहीं हो सकेंगे। यानि बच्चो में कम वज़न और उनकी शारीरिक वृद्धि में रुकावट जैसी विसंगतियों से हमें अभी लंबे समय तक जूझना होगा। अगर भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 पर ग़ौर करें तो भारत में बाल कुपोषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आधे से अधिक राज्यों में बच्चों में बौनेपन और आयु के साथ वज़न में कमी जैसी समस्याओं में वृद्धि हुई है। हैरानी की बात यह है कि यह समस्या गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल जैसे राज्यों में है। ज़ाहिर है, सरकारें बच्चों को ज़रूरत के मुताबिक पौष्टिक आहार मुहैया करा पाने में नाकाम रही है। यह विडंबना ही है कि खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में शिखर पर खड़े हैं, सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है, फिर भी दुनिया के सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे भारत में है। हालांकि बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए स्कूलों में मध्याह्न और पोषण माह जैसी कोशिशें देखने को मिली हैं। अब मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) रखने जैसी कवायद कुपोषण से निपटने के लिए सरकार की छटपटाहट की तस्दीक करती है।

कुपोषण एक जटिल समस्या है और इसका सीधा संबंध कुपोषित बच्चों के परिवारों की आजीविका से भी है। जब तक ग़रीब परिवारों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, जब तक कुपोषण की समस्या से लड़ पाना संभव नहीं है। लिहाज़ा कुपोषण की पहचान वाले परिवारों को जनवितरण प्रणाली एवं मनरेगा के तहत सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। सरकार भले 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का दावा कर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, लेकिन इसकी जांच आवश्यक है कि यह अनाज ज़रूरतमंदों को मिला भी या नहीं।

भुखमरी जैसे सूचकांकों में पिछड़ने पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकारों में अक्सर बढ़ती आबादी को दोष देकर पल्ला झाड़ लेने की प्रवृत्ति देखी जाती है। वैसे भी देश की कई समस्याओं का ठींकरा बढ़ती जनसंख्या पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन इस भूखमरी सूचकांक ने इन सभी बेबुनियाद दावों की पोल खोल दी है। अभी भारत की आबादी करीब एक अरब पैंतीस करोड़ है, जबकि चीन की आबादी करीब एक अरब इकतालीस करोड़। मगर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला यह देश इस सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों की जमात में शामिल है। चीन को शीर्ष 18 देशों में जगह मिली हैं लेकिन चिंता की बात है कि भारत नीचे से 18 देशों में शामिल हैं।

भारत में भूख की गंभीर स्थिति के पीछे वजह कल्याण योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और खानापूर्ति जैसी दिक्क़तें हैं। 2018 में शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की एक रिपोर्ट से पता चला कि बिहार और उत्तर प्रदेश में लगभग आधे बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाता है। बिहार में प्राथमिक स्तर पर उनतालीस फीसद और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 44 प्रतिशत, जबकि उत्तर प्रदेश में 44 प्रतिशत जबकि उत्तर प्रदेश में क्रमशः 41 और 47 फीसद बच्चे मध्याह्न भोजन से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी लगभग आधे बच्चों को मध्याह्न भोजन नसीब नहीं होने की बात कही गई है।

दरअसल, कुपोषण की इस भयावह तस्वीर को बदलने के लिए संजीदगी भरी कोशिशों की ज़रूरत है। मसलन आईसीडीएस (पोषण), पीडीएस (आहार), मनरेगा (रोज़गार) आदि योजनाओं पर ठोस तरीक़े से अमल की ज़रूरत है। कुपोषण एक जटिल समस्या है और इसका सीधा संबंध कुपोषित बच्चों के परिवारों की आजीविका से भी है। जब तक ग़रीब परिवारों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, जब तक कुपोषण की समस्या से लड़ पाना संभव नहीं है। लिहाज़ा कुपोषण की पहचान वाले परिवारों को जनवितरण प्रणाली एवं मनरेगा के तहत सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। सरकार भले 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का दावा कर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, लेकिन इसकी जांच आवश्यक है कि यह अनाज ज़रूरतमंदों को मिला भी या नहीं। ऐसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते लोगों तक अनाज न पहुंचना कोई नई बात नहीं है। स्कूलों में छात्रों की फर्जी हाज़िरी लगाकर उनके नाम पर मध्याह्न भोजन

बाक़ी पेज 11 पर

पेगासस ब्लैकलिस्ट : बढ़ी एनएसओ की मुसीबतें

जैसे ही पेगासस स्पाइवेयर विवाद की जांच कर रहे सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने अपनी जांच शुरू की, संयुक्त राष्ट अमेरिका से एक दिलचस्प ख़बर आई है। पेगासस बनाने वाली इस्राईली कंपनी एनएसओ को बाइडेन प्रशासन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। एक मीडिया कंसोर्टियम ने जैसे ही यह खुलासा किया था कि इस स्पाइवेयर का इस्तेमाल संवेदनशील फोन हैक करने के लिये किया गया था, दुनियाभर में राजनीतिक तूफान आ गया था। पेगासस स्पाइवेयर के निर्माताओं को काली सूचि में डालने का मतलब है कि एनएसओ अब अमेरिकी हार्डवेयर और साफ्टवेयर आयात नहीं कर सकता है। अमेरिका के इस क़दम से कंपनी को प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण स्रोत से वंचित होना पड़ेगा। इससे पेगासस का निर्यात संकट में पड़ सकता है क्योंकि अमेरिका द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने से स्पाइवेयर की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इस निर्णय के बारे में असामान्य बात यह है कि अमेरिका शायद ही कभी उन देशों की फर्मों और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करता है जिन्हें अमेरिका का सहयोगी माना जाता है। अमेरिका नियमित रूप से चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करता है क्योंकि वह चीन को एक ख़तरा और प्रतिद्वंदी मानता है। दूसरी ओर, इजराइल अमेरिका का करीबी और महत्वपूर्ण सहयोगी है जिसका स्थापना के बाद से ही अमेरिका उसकी रक्षा और समर्थन करता रहा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कहा कि प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद निर्णय लिया गया था कि विदेशी सरकारों द्वारा पेगासस हैकिंग टूल का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों, व्यापारियों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और दूतावास के कर्मचारियों को दुर्भावनापूर्ण रूप से लक्षित करने के लिए किया गया था। अमेरिकी सरकार का यह कदम कंपनी के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकता है और दुनियाभर की सरकारें पेगासस स्पाइवेयर की खरीद और उपयोग पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका के फैसले का भारत और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पर क्या असर पड़ता है।

ख़ास ख़बरें

कैपिटल हिंसा पर ट्रंप के छह अहम सहयोगियों को समन

वाशिंगटन: अमेरिका में छह जनवरी को कैपिटल (संसद भवन) हिंसा की जांच कर रही सदन की समिति ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के छह और सहयोगियों को समन जारी किया है। समिति अध्यक्ष बेनी थॉमसन ने कहा कि समिति इन अफसरों से गवाही और दस्तावेज़ मांग रही है।

कनाडा की महिला 'जलवायु परिवर्तन' की पहली मरीज़

कनाडा: कनाडा की 70 वर्षीय एक महिला को जलवायु परिवर्तन का पहला मरीज़ माना जा रहा है। डाक्टरों ने महिला के स्वास्थ्य की इस हालत के लिए इस वर्ष के शुरू में कनाडा में घातक गर्मी और लू को ज़िम्मेदार माना है। महिला की स्वास्थ्य जांच करने वाले कूटेने लेक अस्पताल के विशेषज्ञ ने बताया कि गर्मी व लू के के कारण लोग अचानक स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। महिला रोगी स्वास्थ्य समस्याएं और बदतर हो चुकी हैं।

ईरानी नेता को गरीबी से जोड़ तो अख़बार बंद

दुबई : ईरान में एक अख़बार पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि इसके पहले पेज पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई जैसे दिखने वाले हाथ का ग्राफिक चित्र बनाया गया था। ईरान की ग़रीबी रेखा को दिखाते हाथ को लेकर दैनिक अख़बार 'केलिद' बंद कर दिया गया है।

सिंगापुर अदालत ने कोरोना से ग्रस्त भारतवंशी की फांसी रोकी

सिंगापुर: सिंगापुर की शीर्ष अदालत ने भारतीय मूल के मलयेशियाई व्यक्ति नागेन्द्र के॰ धर्मलिंगम को दी जाने वाली फांसी की सज़ा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मादक पदार्थों की तस्करी के लिए दोषी ठहराए गए नागेन्द्र को चांगी जेल में फांसी दी जानी थी लेकिन उसे कोविड-19 पाजिटिव पाए जाने के बाद फांसी का निष्पादन रोक दिया गया है बताया जाता है कि नागेंद्र मानसिक रूप से विकलांग भी हैं।

साइबर अपराध पर वैश्विक कार्रवाई में दो संदिग्ध हैकर गिरफ्तार

वाशिंगटन: साइबर अपराध के ख़िलाफ़ विश्वव्यापी कार्रवाई के तहत 'रैंसमवेयर' हमलों के सिलसिले में दो संदिग्ध हैकरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साइबर हमलों से 5000 कम्प्यूटर संक्रमित हुए थे। ये गिरफ्तारियां रोमानियाई अफसरों ने की। हैकरों के नाम गुप्त रखे गए हैं। साइबर अपराधी दुनियाभर की सरकारों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं।

इस्लाम में बच्चों के शौक़ पूरे करना

मोहब्बत, बदकारी, यौनाचार के अवगुण जो पनप रहे हैं, यह सब इसी के परिणाम हैं। मगर हम हैं कि आयत करीमा (अनुवाद) ''इनके दिल में जो समझते नहीं और आंखें हैं जो देखती नहीं और कान हैं जो सुनते नहीं, यह लोग जानवरों जैसे हैं बल्कि इन से भी गए गुज़रे का प्रतीक बने हुए हैं। शराब व बलात्कार हमें किसी तरह अवश्य गुनाह महसूस होते हैं मगर हमारे दिलों से इस टीवी के गुनाह और बदकारियां होने का अहसास बिल्कुल समाप्त हो चुका है।

बच्चों के इसी तरह के अच्छे बुरे शौक को पूरा करने का परिणाम है कि मुसलमानों के बच्चों में बालिग (व्यस्क) और बड़े होने के बाद दीन का कुछ शऊर व अहसास पैदा हो तो हो मगर बचपन में वह किसी भी तरह से मुसलमान नज़र नहीं आते, शक्ल व सूरत लिबास और स्वरूप से लेकर इनके विचार और वरीयता वाले कार्यों तक में कहीं भी दीन और दीनी शिक्षाओं की कोई झलक और छाप नज़र नहीं आती, इनकी ज़बानों पर हर समय फिल्म की स्टोरी और फिल्म के स्टारों के चर्चे होते हैं। इनको किसी बड़े से बड़े सहाबी का नाम और इनका कोई कारनामा चाहे याद न हो मगर फिल्म के छोटे-बड़े हीरों के नामों की सूचि उनकी भूमिका के साथ उनके दिलों में रहती हैं। कुरआन करीम की छोटी-छोटी सूरतें और दुआएं कलमें गर इनसे सुनें जाएं तो शायद ही कोई सुना पाए लेकिन उन्हें किसी भी फिल्म का गाना, डांस की स्थिति के साथ इस तरह समाया होता है कि सुनने और देखने वाले को एक बार को यह शक ज़रूर हो जाता है कि शायद इसने भी इस फिल्म में कोई भूमिका अदा की है। बच्चे के किस शौक को पूरा किया जाए और किस शौक को नहीं ? शरीअत में इस सिलसिले में स्पष्ट हिदायतें (निर्देश) मौजूद हैं। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) फरमाते हैं :-''एक बार हज़रत हसन (रज़ि॰) ने जो अभी बच्चे ही थे। सदक़ा की खजूरों में से एक खजूर उठा कर अपने मुंह में रख ली। हुजूर (सल्ल॰) ने देखा तो फरमाया ..थू-थू,,उसको फेंकों, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम बनू हाशिम सदक़ा का माल नहीं खाते।'' (जामअ-अल-उसूल)

हज़रत उमर बिन अबु सल्लमा, जो जोजा-ए-रसूल अल्लाह (सल्ल॰) के पूर्व शौहर के बेटे हैं फरमाते हैं ' मैं हुजूर अकरम (सल्ल॰) के संरक्षण में परवरिश पा रहा था एक रोज़ खाना खाते हुए मेरा हाथ प्लेट में चारों ओर घूम रहा था, (यानि कभी कहीं से और कभी कहीं से खा रहा था) तो हुजूर (सल्ल॰) ने फरमाया कि खाना खाते समय बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाएँ हाथ से खाना खाओ और अपने सामने से खाओ। वह फरमाते हैं कि फिर मैंने इसी तरह (बताए हुए) खाने के तरीके को अपना मामूल बना लिया। (जामअ-अल-उसूल)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि॰) फरमाते हैं कि हुजूर अकरम (सल्ल॰) ने इरशाद फरमाया :'अपनी औलाद को सात साल का हो जाने पर नमाज़ की ताक़ीद करो और दस साल का हो जाने पर इनको (अगर वह नमाज़ न पढ़ें) मारो और (इस उम्र में) इनके बिस्तर अलग कर दो। (जामअ-अल-उसूल)

इन्हीं रिवायतों के दृष्टिगत फिक़्हा हज़रात ने भी लिखा है कि 'शिक्षा व दीक्षा के उद्देश्यों से बच्चे की

माँ-बाप अगर इस अमानत के हुकूक़ अदा करने में सफल हो जाते हैं और बच्चों की वह तरबीयत (दीक्षा) कर जाते हैं जो शरअन होनी चाहिए तो फिर यह औलाद मां-बाप के लिए दुनिया व आख़िरत में राहत व सुकून का माध्यम होगी ही इसके साथ-साथ वह मां-बाप के लिए सदक़ा जारिया भी होगी।

गलतियों पर डांट फटकार की जाएगी। इसीलिए उन्होंने बच्चे को रेशम या सोना पहनाने, इस के हाथ पांव पर मेहंदी लगाने, इसको शराब पिलाने और पेशाब या पखाना के वक़्त क़िब्ले की तरफ चेहरा या पीठ करके बैठलाने को ममनूअ (मना) क़रार दिया है। बल्कि फरमाया है कि हर वह चीज़ जो बड़ों के लिए ममनूअ (मना) और अवैध है बच्चों से भी इसको कराना ममनूअ व अवैध ही है।'

हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मौहम्मद ज़करिया साहब (रह॰) ने ''आप बीती'' में अपने बचपन का एक वाकेआ (घटना) ज़िक्र किया है कि ''मेरी उम्र तीन चार साल की थी, अच्छी तरह से चलना भी बेतकुल्लुफ नहीं सीखा था, सारा दृश्य खूब याद है और ऐसी बातें और वाकये ज़हन में समायी होते हैं, मेरी वाल्दा नूरूलल्ला मरकदहा को मुझ से मोहब्बत थी, मां को मोहब्बत हुआ ही करती है, मगर जितनी मोहब्बत इनको थी अल्लाह इनको बहुत दर्जे अता फरमाए। मैंने माँओं में बहुत कम देखी, उस वक्त उन्होंने मेरे लिए एक खूबसूरत तकिया छोटा सा सिया था, एक बालिश्त, मेरी मौजूदा बालिश्त से चौड़ा और डेढ़ बालिश्त लम्बा, इसकी स्थिति (स्वरूप) भी कभी नहीं भूलूंगा, इसके ऊपर गोटा, ठप्पा, गोखरू, किरन बनत इत्यादि सब ही कुछ जड़ा हुआ था, नीचे लाल कन्द का ग़िलाफ़ और उस पर सफेद जाली का झाला बहुत ही खुशनुमा वह मुझे तो इतना महबूब (प्रिय) था कि बजाए सिर के वह मेरे सीने के ऊपर रहा करता था, कभी इसको प्यार करता, कभी सीने से चिपटाया करता, वालिद साहब ने आवाज़ देकर फरमाया कि ज़करिया मुझे तकिया दे दे, मुझ में वालिद की मोहब्बत ने जोश मारा और अपने नजदीक (तरफ से) अत्याधिक क़ुर्बानी पेश करने की नियत से मैंने कहा कि ''मैं अपना तकिया ले आऊं'' फरमाया कि वरे (इधर) आ। मैं अत्याधिक शोक व ज़ौक में कि अब्बा जान इस नियाज़मन्दी और सआदतमंदी पर बहुत खुश होंगे दौड़ा गया उन्होंने बाएं हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़ कर और दाएं हाथ से मुंह पर ऐसा जोर से थप्पड़ मारा कि आज तक तो इसकी टीस स्वाद भूला नहीं और मरते वक़्त तक उम्मीद नहीं कि भूलूंगा और यूं फरमाया कि ''अभी से बाप के माल पर यूं कहता है कि अपना लाऊं कुछ कमा कर ही कहना कि अपना लाऊं'' अल्लाह ही का फज़ल व करम है और सिर्फ उस का ही अहसान है कि उसके बाद से जब भी यह वाक्या याद आ जाता है तो दिल में यह मज़मून पुख़्ता होता चला जाता है कि अपना इस दुनिया में कोई माल नहीं और अल्लाह का शुक्र है कि दिन प्रतिदिन यह सबकुछ मजबूत ही होता जा रहा है। (पृ॰ 18-19)

हुजूर (सल्ल॰) के इर्शादात : हज़रात फिक़्हा के कलाम और उपरोक्त वाक्ये से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चे के किसी भी बड़े या झूठे अमल को सिर्फ ''शौक़'' समझ कर नज़रअंदाज़ न किया जाए, बल्कि उसकी हर हरकत और उसके हर क़ौल (कथन) व फेल (कार्य) पर बड़ी बारीकी के साथ नज़र रखी जाए वह जो भी शरीअत के ख़िलाफ़ कार्य या अदब के ख़िलाफ़ काम या इसकी मांग करे तो पहले चरण में रोक-टोक व डांट-फटकार से काम लिया जाए इससे भी अगर बाज़ न आए तो फिर पीटने से भी न बचा जाए। इसका कारण यह है कि बच्चों की दीक्षा का मामला गंभीर स्थिति वाला है यह एक अमानत है जिसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा।

माँ-बाप अगर इस अमानत के हुकूक़ अदा करने में सफल हो जाते हैं और बच्चों की वह तरबीयत (दीक्षा) कर जाते हैं जो शरयन होनी चाहिए तो फिर यह औलाद मां-बाप के लिए दुनिया व आख़िरत में राहत व सुकून का माध्यम होगी ही इसके साथ-साथ वह मां-बाप के लिए सदक़ा जारिया भी होगी। यह औलाद जितने नेक अमल करेगी, सबका अज्र व सवाब मां-बाप के आमाल में दर्ज होगा और अगर खुदा न ख़्वास्ता इनकी तरबीयत में किसी तरह का कोई नुख़्स (कमी) खामी रह गयी जिसके परिणाम में इनकी तबियत में शरीअत से दूरी और दीन से बेज़ारी (अरूचि) पैदा हो गयी तो फिर यह औलाद दुनियावी लिहाज़ से यानि किसी दर्जे में राहत का कारण हो भी जाए मगर आख़िरत की दृष्टि से ऐसी औलाद सरासर वबाले जान है यह जितने ख़िलाफे शरयी मामलों का बोलबाला करेगी, इनका गुनाह न सिर्फ यह कि मां-बाप के नामा- ए-आमाल में लिखा जाएगा बल्कि क़यामत में यही औलाद अपनी बद दीनी का ठीकरा भी अपने मां-बाप के सिर फोड़ेगी और उन्हीं को इसका दोषी ठहराएगी इसलिए यह ज़हन नशीनी (ध्यान में) रहना चाहिए कि औलाद सकूने दिल भी है और वबाल जान भी! इसकी सही तरबियत जन्नत का रास्ता है और ग़लत तरबीयत जहन्नुम का रास्ता। अब यह मां-बाप पर निर्भर है कि वह कौन से रास्ते का चयन करते हैं।❑❑

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल अदियात नं॰ 100)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

कि निःसंदेह इंसान अपने पालनहार का नाशुक्रा है।

अर्थात् जिहाद करने वाले सवारों को अल्लाह के लिए जान देना बताती है कि वफादार और धन्यवाद देने वाले बंदे ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अल्लाह की दी हुई शक्तियों को उसके रास्ते में ख़र्च नहीं करता, वह उच्च कोटि का मूर्ख और कृतघ्न है, बल्कि ध्यानपूर्वक देखो तो घोड़ा अपने कार्यों से गवाही दे रहा है कि जो लोग वास्तविक मालिक की दी हुई रोज़ी खाते और उसकी असंख्य नेअमतों से दिन-रात लाभान्वित होते हैं इस सबके बाद भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, वे पशुओं से भी अधिक अपमानित और तुच्छ हैं। एक असील घोड़े को मालिक घास के तिनके और थोड़ा सा दाना खिलाता है वह इतनी सी देखभाल पर अपने मालिक की वफादारी में जान अड़ा देता है जिधर सवार संकेत करता है उधर दौड़ पड़ता है और हांफता हुआ टापे मारता और गर्द उड़ाता हुआ घमासान लड़ाईयों में बिना झिझक घुस जाता है। गोलियों की बारिश में तलवारों और संगीनों के सामने पड़ने पर छाती नहीं फेरता बल्कि कभी कभी वफादार घोड़ा सवार को बचाने के लिए अपनी जान ख़तरे में डाल देता है। क्या इंसान ने ऐसे घोड़ों से कुछ सबक़ सीखा? कि उसका भी कोई पालने वाला मालिक है जिसकी वफादारी में उसे जान और मार्च ख़र्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वास्तव में इंसान बड़ा मूर्ख और कृतघ्न है यदि एक घोड़े और कुत्ते के बराबर भी वफादारी नहीं दिखा सकता।

और उसको स्वयं भी इसकी ख़बर है।

अर्थात् जान पर खेलने वाले मुजाहिदों की और उनके घोड़ों की वफादारी और धन्यवाद आंखों के सामने है फिर भी निर्लज्ज टस से मस नहीं होता। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि मनुष्य नाशुक्री पर गवाही दे रहा है ज़रा अपने हृदय की ओर कान लगाये तो सुन लेगा कि अंदर से उसका हृदय कह रहा है कि तू बड़ा नाशुक्रा है।

और वह माल की मुहब्बत में बहुत पक्का है।

अर्थात् ईर्ष्या लालच कंजूसी ने उसको अंधा बना रखा है। दुनिया के माल धन की मुहब्बत में इतना डूब गया है कि वास्तविक नामतें देने वाले को भी भूल बैठा है नहीं समझता कि आगे चलकर इसका क्या परिणाम होने वाला है।

क्या वह उस समय को नहीं जानता जब ज़िन्दा किये जायेंगे। जितने मुर्दे कबों में हैं और प्रत्यक्ष हो जायेगा जो कुछ कि दिलों में है।

अर्थात् वह समय भी आने वाला है जब मुर्दा शरीर कब्रों से निकाल कर ज़िन्दा किये जायेंगे और दिलों में जो चीज़ें छिपी हुई हैं सब खोलकर रख दी जायेंगी। उसी समय देखें यह माल कहां तक काम देगा और मूर्ख कृतघ्न लोग कहां छूटकर जायेंगे। अगर यह निर्लज्ज इस बात को समझ लेते तो कभी माल की मुहब्बत में डूबकर ऐसा काम न करते।

रुकू नं॰ 1

निःसंदेह उनके पालनहार को उस दिन की सब खबर है।

अर्थात् हर प्रकार से अल्लाह का ज्ञान हर समय बन्दे की प्रत्यक्ष और परोक्ष बातों को घेरे हैं परंतु उस दिन उसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्यक्ष हो जायेगा और किसी को इंकार करने की संभावना न रहेगी।

इंदिरा गाँधी की राजनीतिक विरासत और प्रियंका के मज़बूत इरादे

डॉ॰ उदित राज

यह ज़रूरी नहीं कि औलाद अपनी पूर्वज की ऊंचाई तक पहुंच सके। बहुत सारे मामलों में दूर-दूर तक कोई लक्षण नहीं होते जो पूर्वजों में हुआ करते हो। हाल में प्रियंका गांधी की कार्यक्षमता और प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह अपनी दादी इंदिरा गांधी के पदचिह्नों पर चल रही हैं।

हाथरस में दलित बच्ची की बलातकार-हत्या मामले में जो बहादुरी और विवेक दिखाई उससे इंदिरा गांधी के लक्षण दिखने लगे थे। इंदिरा गांधी बेल्छी-बिहार मारे गए दलितों को विषम परिस्थितियों में देखने गई थीं जो राष्ट्रीय मुद्दा बना। हाल में लखीमपुर खीरी में कुचले गए किसान और आगरा में पुलिस कस्टडी में दलित की हत्या के मुद्दे को जिस तरह से उठाया और लड़ा, कोई संशय नहीं रह गया कि ये दूसरी इंदिरा गांधी नहीं हैं।

हाथरस के मामले में जाते वक़्त जब देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस लाठियों से पीठ रही थी तो बिना समय गवाएं दौड़कर पुलिस के लाठी डंडे के सामने खड़ी हो गई और उनका बचाव किया। यह असाधारण साहसिक क़दम था। एक घटना मुझे और स्मरण में आ रही है कि सपेरे के साथ बैठ कर सांप को बहुत सहजता से देखा और छुआ जबकि साधारण व्यक्ति दूर से ही देख कर डर जाता है।

सफलता व्यक्ति की दृढ़ता बौद्धिक क्षमता और दूरदर्शिता पर निर्भर करता ही है लेकिन कई बार परिस्थितियों की भूमिका कहीं ज़्यादा होती है। प्रियंका गांधी जिन परिस्थितियों में लड़ रही हैं परिस्थितियां पक्ष में नहीं दिखती। यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रादुर्भाव, सफलता एवं वर्तमान पर चर्चा किये बग़ैर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

कांग्रेस पार्टी की स्थापना विदेशी ताक़त अंग्रेजों के ख़िलाफ़ थी और उस समय जाति-धर्म और क्षेत्रवाद आड़े नहीं आया। स्वतंत्रता आंदोलन में कमोबेश सबकी भागीदारी थी इस तरत से अपनों से लड़ने की इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी। अंग्रेज क्रूर और तानाशाह ज़रूर थे जो सामने दिखता था उनके ख़िलाफ़ कांग्रेस पार्टी लड़ती गयी और जीतती गयी। सबसे ज़्यादा चुभने वाली वो बात है जो आज कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? जब से भारत भूमि-पे मानव इतिहास की जानकारी है, स्वतंत्रता आंदोलनकारियों कि तुलना में न पहले की पीढ़ी और बाद की उतनी कुर्बानी दी हो। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के बारे में कहा जाता था कि उनके राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता था। जब भविष्य के नतीजे के बारे में ना पता हो तो ऐसे में अपनी ज़िन्दगी जेल या मौत के हवाले कर देना कोई साधारण बात नहीं है। नेहरू जी लगभग नौ साल जेल में थे और गांधी जी सात साल। क्या इनको पता था कि कभी जेल से छूटेंगे? उस समय किसी को भी भविष्य का अनुमान नहीं था। प्रियंका गांधी ऐसी वारिस की उपज है।

वर्तमान में जिनके ख़िलाफ़ लड़ाई है उन्होंने झूठ, दुष्प्रचार, धनशक्ति, मीडिया नियंत्रण, धोखेबाज़ी और जासूसी का सहारा लिया है, अंग्रेज़ संशोधनों का शोषण करने आये थे वो दिख रहा था और उनको रोकने जो आता था बल प्रयोग और विभाजन की नीति अपनाते थे, कुछ मायनों में वो लड़ाई सीधी थी अब तो आंतरिक कुटिल - कमीन शक्तियों से लड़ना पड़ रहा है।

देश में तमाम क्षेत्रीय दल और राजनेता हैं लेकिन प्रमुख मुद्दे पर क्यों नहीं कुछ करते और बोलते हैं। चीन भारत में घुसपैठ करके बैठा हुआ है, क्या राहुल की ही चिंता है? ऑक्सीजन, दवा व बेड न मिलने से लाखों लोग मर गए, कांग्रेस पार्टी के अलावा क्षेत्रीय पार्टियों ने इस मुद्दे को ठीक से उठाया भी नहीं।

संविधान बचाने की बात, सरकारी संपत्ति की बिक्री, मानवाधिकार का हनन और सरकारी संस्थाओं का अतिक्रमण..क्या ये चिंता केवल कांग्रेस की है? ऐसा भी नहीं है कि क्षेत्रीय दल या सिविल सोसायटी को बेचैनी नहीं हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। एक प्रकार बार-बार किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? यह बता देना चाहिए कि आज़ादी से लेकर 2014 की परिस्थिति में ही सबको राजनीति करने का अनुभव व तरीक़ा था लेकिन उसके बाद परिस्थितियां इतने ज़्यादा बदल गयीं जिसमें विपक्ष डर और सहम गया। जिसने आवाज़ उठायी, उनके ख़िलाफ़ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आदि मशीनरी का बर्बरता से इस्तेमाल किया गया। इसे और बेहतर समझने के लिए 2012-13 के आंदोलन पर नज़र डालनी पड़ेगी।

रामलीला मैदान के 9 दिन के आंदोलन को लगभग सारे चैनल ने सरकार के ख़िलाफ़ लाइव दिखाया, आज हालत यह है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रेस कांफ्रेंस को भी लाइव नहीं दिखाया जाता। उस समय के अख़बारों को उठाकर देखा जाय तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की ख़बर न के बराबर होती थी और लगभग 2011 से विभिन्न मुद्दे कोल व 2-जी स्प्रैक्ट्रम घोटाले के मुद्दे पर उस समय की सरकार के ख़िलाफ़ लिखने के अलावा कोई और ख़बर शायद ही होती थी। बाद में दोनों आरोप निराधार साबित हुए, यह जवाब उनके लिए हैं जो कहते हैं कांग्रेस क्या कर रही है? उनको यह बात और जाननी चाहिए कि उस समय की सिविल सोसायटी अन्ना आंदोलन की ताक़त थी, जो आज बिल में घुस गयी है। शासन-प्रशासन और विकास को लेकर राजनीति होती तो कांग्रेस 2019 में ही सरकार बना लेती और भाजपा चुनाव न जीत पाती। संघ की विचारधारा की राजनीतिक सत्ता सामाजिक और सांस्कृतिक के मुक़ाबल से तुच्छ है और यहीं पर विपक्ष कमज़ोर पड़ जाता है।

राम मंदिर बनाना, धार्मिक आयोजन, इस्लाम से हिन्दू धर्म की रक्षा, भारत सोने की चिड़िया था और पुनः बनाना आदि के प्रचार के सामने रोज़गार, विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि महत्वहीन लगते हैं। आम जनता को स्वर्ग व नर्क सपना दिखाकर भ्रमित व ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है। इतनी विषम परिस्थितियों से इंदिरा गांधी को जूझना न पड़ा होगा जितना कि प्रियंका गांधी को। यह कहना कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी के प्रतिमूर्ति हैं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। एक दिन इंदिरा गांधी का स्थान लेंगी, ऐसा लगने लगा है। ❑❑

प्रियंका की बढ़ती सक्रियता क्या कांग्रेस को लाभ होगा

कांग्रेस महासचिव श्रीमति प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 40 प्रतिशत टिकट महिला प्रत्याशियों को देने की घोषणा की है उससे इस राज्य की राजनीति पर गुणात्मक असर पड़ सकता है क्योंकि पिछले तीस साल से देश के इस सबसे बड़े राज्य की राजनीति संकीर्ण विभाजनकारी सामाजिक मुद्दों के चारों ओर ही घूम रही है जिससे इस प्रदेश की छवि प्रतिगामी सियासत के सूरमा की बनी हुई है। तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण भारत का राजनीतिक 'विमर्श' तय करने वाला प्रदेश भी है क्योंकि इसकी सामाजिक संरचना भारत के इतिहास के उन विभिन्न चरणों की उत्तराधिकारी है जिनमें सामाजिक आर्थिक प्रगति के सिलसिले क्रमवार चलते रहते हैं। एक ओर यह घनघोर जातिवाद से ग्रस्त तो दूसरी ओर सामंतवाद से त्रस्त विरासत को ढोता रहा है तो तीसरी ओर इसी की सरज़मीं से औद्योगिक क्रांति से जन्मी प्रगतिशीलता इसकी धरोहर रही है। आज़ादी के बाद के कुछ दशकों तक इसी प्रदेश का 'कानपुर' शहर भारत का 'मैनचेस्टर' कहलाया करता था परंतु 80 के दशक के बाद यह राज्य भारत की राजनीति की ऐसी प्रयोगशाला बना जिसमें धार्मिक व जातिगत पहचान ने शीर्षस्थ स्थान इस प्रकार लिया कि विचारधारात्मक रूप से समाज के सर्वांगिण विकास का भाव लुप्प होता चला गया और समाज का कबायली स्वरूप ऊपर आने लगा। निश्चित रूप से इसमें राम मंदिर आंदोलन और मंडल आयोग ने निर्णायक भूमिका निभाई।

प्रियंका गांधी ने राजनीति की इस रफ्तार को मोड़ने का जो प्रयास किया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए और जाति-धर्म से ऊपर उठ कर सकल समाजोत्थान के बारे में विचार किया जाना चाहिए। इससे सैद्धांतिक व वैचारिक आधार पर राजनीति को नये कलेवरों में बांधने की शुरुआत तभी हो सकती है जबकि पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी ने महिला सशक्तीकरण का वह कार्ड खेला है जिसमें हर समाज को फिर से वैचारिक रूप से गोलबंद करने की क्षमता है।

उत्तर प्रदेश के संबंध में हमें विचार करना चाहिए कि 1963 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पं॰ जवाहर लाल नेहरू ने कामराज प्लान लागू करके मठाधीश बने कांग्रेस नेताओं का इस्तीफा लिया था तो राज्य के लौहपुरुष कहे जाने वाले स्व. चन्द्रभानु गुप्ता मुख्यमंत्री थे। कामराज प्लान के तहत श्री गुप्ता के स्थान पर स्व. श्रीमति सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया। उनके बैठने से राज्य की कांग्रेस पार्टी में गुटबाज़ी पर विराम लगा और राजनीति में सदाचारिता की बातें होने लगीं। हालांकि इसके बाद 1971 में कांग्रेस पार्टी के भीतर स्व. चौधरी चरण सिंह ने विद्रोह का बिगुल इसी वजह से बजाया कि सत्ता के शीर्ष पर केवल कुछ संभ्रांत कहे जाने वाले लोगों का एकाधिकार नहीं हो सकता परंतु उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर वह राजनीतिक विमर्श खड़ा किया जिससे भारत का ज़मीनी धरातल से सर्वांगिण विकास हो सके जिसके लिए उन्होंने बापू के गांवों के विकास के दर्शन को आगे रखा और कहा कि गांवों की कीमत पर शहरों का विकास करके हम भारत का विकास नहीं कर सकते।

आज बदले हुए संदर्भों में प्रियंका गांधी भी वही बात कह रही हैं कि जाति और धर्म में बांट कर हम उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते परंतु कांग्रेस पार्टी को पंजाब में अपने गिरेबान में भी झांकना होगा जहां उसके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी अलग पार्टी गठित करने का ऐलान कर दिया है। कैप्टन भूल रहे हैं कि वह कोई व्यापक जनाधार वाले नेता नहीं हैं उनका जनाधार इतना ही है कि वह पंजाब की शीर्ष राजनीति में कांग्रेस में रहते हुए पटियाला राजघराने के प्रतीक के वैभव की आभा में आम कांग्रेसियों का भरपूर समर्थन प्राप्त करते और राज्य में कांग्रेस के एक सशक्त विकल्प के रूप में होने का लाभ उठाते रहे हैं। निश्चित रूप से वह न तो चौधरी चरण सिंह हैं और न ही ममता बनर्जी या जगन रेड्डी न अरविंद केजरीवाल जो अपने पुरुषार्थ से जनता के बीच लोकप्रिय हुए। उनके लोकप्रिय होने का एकमात्र कारण उनका कांग्रेसी होना था। अतः उनकी नई पार्टी का भाजपा या आकली दल (एसएस ढींढसा गुट) से सहयोग करने का असर केवल इतना ही पड़ेगा कि वह पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के टिकट पाने को आतुर नाकामयाब प्रत्याशियों को अपनी ओर खींच सकेंगे। मगर ऐसा करके वह केवल पंजाब में अस्थिरता को ही दावत दे सकते हैं, अतः पंजाब राज्य की जनता की राजनीतिक बुद्धि को वह एक मायने में चुनौती भी देंगे क्योंकि यह सीमांत राज्य है जिसमें राजनीतिक स्थायित्व की ज़रूरत है और इस हक़ीक़त को आम पंजाबी बख़ूबी समझता है। कैप्टन को ग़लतफहमी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2017 में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था न की कैप्टन के कोई प्रभाव या अधिनायकवाद को। ❑❑

कप्तानी की दौड़ में रोहित आगे पीछे-पीछे राहुल

विश्व कप प्रबल दावेदारों में शामिल भारतीय टीम के सेमीफाइनल में भी जगह बनाने में नाकाम रही। विश्व कप टी-20 में भारत अपने ख़राब प्रदर्शन के चलते टूर्नामेंट से बाहर होकर, सबसे बड़ी हार पाकिस्तान से मिली और उसके बाद का सफर भी कोई ख़ास नहीं रहा, आख़िर टी-20 में स्कॉटलैंड को हराकर सुखद अंत करके टीम इंडिया ने कुछ साख बचाई।

टी-20 विश्व के बाद विराट कोहली क्रिकेट के सबसे छोटे फार्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। यही नहीं, बीसीसी उन्हें वनडे की कप्तानी से भी हटाना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि सफेद गेंद से क्रिकेट में एक कप्तान होना चाहिए और लाल गेंद यानि टेस्ट का अलग कप्तान होना चाहिए।

सूत्रों से पता चला है कि टी-20 के बाद 17 नवंबर से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भारत में होने वाली तीन टी-20 मैचों की सीरीज में रोहित का कप्तान बनना लगभग तय है। केएल राहुल को उपकप्तान बनाया जा सकता है। ऐसी भी संभावना है कि राहुल को कप्तान बना दिया जाए और उपकप्तानी की ज़िम्मेदारी किसी युवा खिलाड़ी को सौंप दी जाए।

अगले कुछ दिनों में बीसीसीआई नेतृत्व व राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के बीच बैठक होगी, जिसमें वनडे कप्तान के तौर पर कोहली के भविष्य पर भी चर्चा की जाएगी। आइसीसी टूर्नामेंट जीतने में एक और विफलता के बाद सीमित ओवरों के प्रारूप में कप्तान के तौर पर कोहली का भविष्य ख़तरे में हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली व सचिव जय शाह जल्द कोई बड़ा फैसला बैठक करके ले सकते हैं।

आस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले आगामी टी-20 विश्व कप के लिए लगभग 11 माह बचे हैं और इस साल भारतीय टीम कोा वनडे सीरीज नहीं नहीं खेलती हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। अगर रोहित आराम करते हैं तो राहुल कप्तान हो सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार फिलहाल रोहित ने खुद को न्यूजीलैंड सीरीज से अलग करने के लिए नहीं कहा है। वह अगर कहेंगे कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ टी-20 मैचों में टीम का नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं तो हम अन्य विकल्पों के बारे में सोचेंगे। एक और अधिकारी ने कहा है कि किसी खिलाड़ी को अगर कप्तानी मिल रही है तो वह आराम क्यों करेंगा। अगर सिर्फ खेलने की बात होती तो रोहित आराम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नए कप्तान के तौर पर इस सीरीज़ में पेश किया जाएग, तो मुझे नहीं लगता कि वह आराम करेंगे। पूर्णकालिक टी-20 कप्तान के रूप में यह उनकी पहली सीरीज़ होगी। वह इस सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कानपुर (25-29 नवंबर) और मुंबई (तीन से सात दिसंबर) में होने वाले दो टेस्ट मैचों से ब्रेक ले सकते हैं।

हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर टीम की ओर से चयनकर्ताओं को ग़लत जानकारी दी गई। इसको लेकर भी बीसीसीआइ ख़फा है। ऐसा माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पांड्या की फिटनेस को लेकर कई लोगों को अंधेर में रखा गया। पांड्या को लेकर कौन किसको ध ोखा दे रहा है। सितंबर में भारत के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने कहा था कि पांड्या हर मैच में अपने कोटे के चार ओवर डालेंगे, लेकिन वह पहले मैच में गेंदबाज़ी की स्थिति में नहीं थे। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच में उनसे दो ओवर डलवाए गए। उनकी ओर भुवनेश्वर कुमार की टिकट भविष्य में टीम से छुट्टी तय है। इन खिलाड़ियों की जगह आइपीएल के 2021 सत्र में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड और बनाने वालों में शामिल आवेश ख़ान व युजवेंद्रा सिंह चहल को मोक़ा मिल सकता हैं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को आराम दिया जाएगा। पांड्या के विकल्प के तौर पर वेंकटेश्वर अय्यर को शामिल किया जा सकता है। टी-20 टीम के लिए जम्मू कश्मीर की नई सनसनी उमरान मलिक, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और दीपक चाहर के नाम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। गिल, मयंक, उमेश यादव टैस्ट टीम में वापसी करने के लिए तैयार है।

युवा खिलाड़ी को कप्तान बनाने पर राहुल हो सकते हैं मजबूत दावेदार

सूत्रों के अनुसार कोहली चाहते है। किसी युवा को टीम का कप्तान बनाया जाए और ऐसे में वह अपने पंसदीदा राहुल को कप्तान बनते हुए देखना चाहेंगे। हालांकि, चयनकर्ता यदि किसी युवा को कप्तान बनाने का फैसला करते हैं तो रोहित की तुलना में राहुल का दावा ज़्यादा मज़बूत होगा। कोहली 33 वर्ष, जबकि रोहित 34 वर्ष के हैं और राहुल 29 वर्ष के हैं। ऐसे में चयनकर्ता राहुल को मौक़ा देकर कप्तानी की दौड़ में लंबे समय के लिए स्थायित्व लाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि राहुल को कप्तान बनाया गया तो किसी युवा को उपकप्तान बनाया जा सकता है और इसके लिए 24 साल के पंत बेहतर है। ❑❑

डिप्रेशन के मामलों में हो रही वृद्धि विशेष सतर्कता की ज़रूरत

देश में मानसिक सेहत के आंकड़े पहले से ही चिंताजनक है, लेकिन बीते डेढ़ दो सालों में कोरोना ने लोगों की मानसिक सेहत पर और भी बुरा असर डाला है। बेचैनी और डिप्रेशन के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई हैं। मानसिक सेहत की अनदेखी न करके हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं।

क्या है डिप्रेशन

अक्सर हम लोग किन्हीं प्रतिकूल कारणों से तनाव में आ जाते हैं और फिर एक अंतराल के बाद सामान्य हो जाते हैं। कुछ समय के लिए तनावग्रस्त होने का मतलब डिप्रेशन नहीं है। एक सीमा तक तनाव हमें अपने वांछित कामों को करने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में डिप्रेशन से आशय उस मनोदशा से है, जिसमें व्यक्ति को घिरा हुआ महसूस करता है। उसे आगे कुछ बेहतरी की उम्मीद ही नहीं होती। डिप्रेशन के मुख्य लक्षणों को हल्के, मध्यम और गंभीर में विभाजित किया गया है।

हल्के और गंभीर लक्षण -

स्वयं को हताशा और दुखी महसूस करना। किसी काम में मन न लगना। लोगों से मिलने जुलने से कतराना। अपनी हॉबी में दिलचस्पी न लेना। सेक्स की इच्छा का काम होते जाना। सोने की आदतों में बदलाव आना, बहुत ज़्यादा सोना या फिर कम सोना। बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना।

गंभीर लक्षण : डॉक्टरी परामर्श ज़रूरी

सफलता हासिल करने की या किसी कार्य को पूरा करने की उम्मीद ही छोड़ देना। यह महसूस करना कि हमारी अब कोई मदद नहीं कर सकता है। जीने का लक्ष्य खत्म हो जाना, यह सोचना कि अब सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं।

अपने भावों पर काबू न कर पाना, बहुत हिंसक हो जाना, बहुत रोना।

आत्महत्या का विचार उठना या फिर मृत्यु के बारे में सोचते रहना।

इलाज के बारे में

सबसे पहले अपपने मनोचिकित्सक से परामर्श लें। काउंसिलिंग के दो प्रकार होते हैं। पहला, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे संक्षेप में सीबीटी कहते हैं दूसरी को वेंटिलेशन थेरेपी कह सकते हैं, जिसका आशय अपने मन की बात को दूसरों के साथ साझा (शेयर) करना है।

वहीं, डिप्रेशन की गंभीर स्थिति वाले मरीज़ों में काउंसिलिंग के साथ एंटीडिप्रेसेंट दवाओं का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा, उन उपायों का भी असर होता है :

जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाएं, योगासन और प्राणायाम करें। ध्यान को अपनी नियमित दिनचर्या में स्थान दें।

लोगों से मिले जुलें सक्रिय रहें। नशे से दूर रहें, इससे डिप्रेशन बढ़ता है। विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही दवाएं लें। सोच सकारात्मक रखें। अच्छा आहार लें। हरी सब्जियां और मौसमी फल खाएं। नियमित व्यायाम करें। धूम्रपान और शराब का सेवन न करें। तनाव व अवसाद नियंत्रित करने के लिए स्मार्टफोन पर इंटरनेट पर कई मेडिकल ऐप्स उपलब्ध हैं, जिससे तनाव में लाभ होता है।

डिप्रेशन व आत्महत्या की प्रवृत्ति

डिप्रेशन का पहला ट्रेंड है एंग्जायटी या मानसिक रूप से बेचैनी महसूस करना। दूसरा ट्रेंड है सुसाइडल होना या मन में आत्महत्या के विचार आना।

डिप्रेशन का तीसरा ट्रेंड है साइकोसिस होना। साइकोसिस में कोई व्यक्ति विभ्रम (हेल्युसिनेशन) से ग्रस्त हो जाता है, जो उसे मेडिकल भाषा में डील्यूजन (अनर्गल या बेवजह शक के विचारों से ग्रस्त होना) का शिकार बना सकती है। मरीज़ सोचता है कि उसे लोग मार डालेंगे, उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी और कोई साज़िश रच रहा है, आदि। मरीज़ के दिमाग़ में कई शक पैदा होने लगते हैं।

इन लक्षणों पर ध्यान दें

अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग आत्महत्या का प्रयास करने के पूर्व परोक्ष रूप से कुछ संकेत देते हैं लेकिन, इस संदर्भ में यह ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें आत्महत्या के पूर्व लक्षणों में शुमार करें। हां, इन लक्षणों के बारे में जानकार हम मानसिक समस्या से जूझ रहे व्यक्ति के व्यवहार व उसके बर्ताव पर नज़र रख सकते हैं। मनोचिकित्सक की मदद ले सकते हैं। नब्बे लोग खुदकुशी करने के संदर्भ में परोक्ष रूप से अन्य किसी व्यक्ति के साथ कभी न कभी आत्महत्या के बारे में बात करते हैं उन्हें यह उम्मीद रहती है कि कोई उन्हें रोकने की सलाह देगा।

वे सीधे तौर पर अपना इरादा ज़ाहिर नहीं करते, पर बात करने की एक कोशिश ज़रूर करते हैं।

आत्महत्या का विचार रखने वाले लोग, जिनसे उनकी अनबन या विवाद हुआ है, उनसे समझौता करने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करता है। ❑❑

रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी

कोरोना महामारी से पहले जो ट्रेनें चलाई जा रही थीं उसे लेकर रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने फिर से रेगुलर ट्रेनों को शुरू करने का ऐलान किया है। कुछ दिनों के अंदर 1700 से ज्यादा ट्रेनें, रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रिस्टोर कर दी जाएंगी। कोरोना की वजह से रेगुलर ट्रेनों पर रोक लगा दी गई थीं। इनकी जगह पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थीं। लेकिन अब कोरोना बहुत हद तक काबू में है ऐसे में रेल मंत्रालय ने पुरानी ट्रेनों को फिर से चलाने का ऐलान किया है। रेलवे की ओर से जारी सर्कुलर में यह भी साफ किया गया है कि गया है अब फिर प्री कोविड वाले रेट लागू कर दिए गए हैं। मतलब यह कि अभी तक जो स्पेशल ट्रेनों के लिए स्पेशल किराया लिया जा रहा था, अब वो बदल जाएगा और फिर रेगुलर किराया ही अब यात्रियों से लिया जाएगा। स्पेशल ट्रेनों के लिए यात्रियों को ज्यादा भुगतान करना पड़ता था।

शेष.... पार्षदों के प्रदर्शन...

चार साल पूरे करने के बाद तीन नगर निगम में एक भी पार्षद ने मुद्दों की गुणवत्ता में 'ए' (100 से 80 के बीच) या 'बी' (80 से कम या 70 से अधिक या उसके बराबर) श्रेणी हासिल कर पाने के योग्य कार्य नहीं कर पाए हैं। यह एक आईना जनता के लिए है जो आने वाले दिनों में इन पार्षदों को अपना बहुमूल्य वोट कुछ सोच समझ कर दे और आंकलन करे कि उक्त पार्षद ने हमारे और क्षेत्र के हित में क्या और कितना कार्य किया और आगे अगर उसको वोट दे तो वह क्या कार्य हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कर पाएगा।

फिलहाल जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनती है ताकि वह उनके क्षेत्र का विकास करे ताकि वह अपने वोट को देकर खुद को ठगा हुआ महसूस न करें, अगर यही जनप्रतिनिधि जनता के विकास कार्य हेतू सजग और संघर्षरत रहते तो शायद आने वाले चुनाव में जनता को इनके बारे में ज़्यादा संकोच दिखाना नहीं पड़ता।

शेष.... माउंटेनियरिंग युवाओं के लिए...

तापमान परिवर्तन की स्थितियों में पर्वतारोहियों को चेतावनी जारी कर जीवन सुरक्षित कर सकें।

ट्रैक ऑर्गेनाइजर : ट्रैक ऑर्गेनाइजर ट्रेकिंग की पूरी व्यवस्था देखता है। इसके लिए ट्रेक आर्गनाइजर अपनी ट्रेक कंपनीज को वेबसाइट्स, यूटयूब से प्रसारित कर उनसे अपने क्षेत्र के लोगों को ट्रेकिंग के लिए आमंत्रित करता है तथा उन्हें पूरा ट्रेकिंग का पूरा प्लान बनाकर देता है तथा उसे एग्जीक्यूटिव भी करवाता है। लाइजन ऑफिसर पद के लिए सरकारी स्तर पर भर्ती की जाती है।

शेष.... कैसे मिले भुखमरी से मुक्ति

की राशि में गोलमाल की ख़बरें कोई नई बात नहीं है। इसलिए अगर स्कूलों में विद्यार्थियों की बायोमैट्रिक हाज़िरी प्रणाली लागू कर दी जाए तो मध्याह्न भोजन योजना में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ राज्यों में इसकी शुरूआत भी हो चुकी है। इसके अलावा पोषणा पुनर्वास केंद्रों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को मज़बूत करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत स्वास्थ्य सेवाओं पर अभी भी अपनी जीडीपी का महज़ तीन प्रतिशत ही ख़र्च करता है, जबकि अमेरिका 16.9, जम्रनी 11.1, जापान 10.9 फीसद ख़र्च करता है।

कुपोषण की समस्या का संबंध ग़रीबी और बेरोज़गारी जैसी समस्याओं से भी जुड़ा है। अगर लोगों को रोज़गार मिले, उनकी आमद बढ़े तो इससे जीवन स्तर में सुधार होगा। लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दें पाएंगे। कम आयु में होने वाली शादियों को रोक कर बच्चों को कुपोषित होने से बचाया जा सकेगा। इन उपायों के साथ-साथ जो सबसे ज़रूरी है, वह यह कि कुपोषण से लड़ाई के लिए सरकार मज़बूत इच्छाशक्ति दिखाए। यह इच्छाशक्ति के अभाव का ही नतीजा है कि सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद चीन शीर्ष बीस देशों में जगह बनाने में सफल हो गया ओर हम सौ से भी नीचे हैं।

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

कॉलेज खोलने की दिशा प्रगति हुई है, लेकिन इस काम में और तेज़ी लाने की ज़रूरत है।

यह भी किसी खुशख़बरी से कम नहीं हैं कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी शुभारंभ किया है। दावा है कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह देश की सबसे बड़ी योजना है। चिकित्सा क्षेत्र में अभी भारत को बहुत लंबा सफर तय करना है। डॉक्टर और मरीज़ अनुपात के अलावा चिकित्सा की आधारभूत सेवाओं का बड़ा अभाव है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की कमियों पर भी ग़ौर करना चाहिए। सरकार की इस योजना की विदेश में भी तारीफ हुई है, लेकिन यह देखना भी ज़रूरी है कि निजी अस्पताल क्या आम गरीब मरीज़ों को पूरा लाभ दे रहे हैं? क्या महामारी के समय अब इन अस्पतालों से कोई भी निराश नहीं लौटेगा? किसी भी विकास को ज़मीनी स्तर पर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकारों को पूरी मुस्तैदी से सेवाओं की निगरानी करनी पड़ेगी।

शेष.... प्रथम पृष्ठ

विकसित करती जाती है जिनमें स्वयं का प्रभुत्व एवं स्वयं का सम्मान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। संभवत: यही पक्ष उन्हें लोकतंत्र व सहिष्णुता के मूल्यों से परे ले जाता है। ऐसे लोग क्रोध व आक्रामकता के साथ अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं और दूसरे समूहों को व उनकी सहिष्णुता को उनकी कमज़ोरी बताते हैं। पर वे ये भूल जाते हैं कि आक्रामकता व हिंसा के सहारे कोई भी समूह या व्यक्ति अल्पकालिक समय के लिए प्रभावी तो हो सकता है लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं हो सकता। उसके अपने समूह ही डरने लगते हैं कि उनकी आक्रामकता और हिंसात्मक प्रतिक्रिया कहीं उनके समूह को ही नुकसान न पहुंचा दे।

एक विकसित लोकतंत्र में विरोध और असहमति किसी भी नागरिक का अधिकार है। उसके इस अधिकार की रक्षा करना राज्य एवं प्रशासन का दायित्व है, न कि उसके विरुद्ध हिंसा या आक्रामक क़दम उठाकर उसे भयभीत करने का प्रयास करना अथवा उसके इस अधिकार का बलपूर्वक दमन करना। नोबल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एक बार इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर रोष व्यक्त करते हुए कहा था कि देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश कम होती जा रही है। साथ ही इस बात से भी इंकार किया जा सकता कि तुलनात्मक रूप से अब हिरासत में मौत की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

यह विरोधाभास ही है कि गांधी जी के सत्य व अहिंसा के जिन मूल्यों को मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्तित्वों ने अपनी जीवन शैली व कार्य प्रणाली में शामिल किया, वही मूल्य अपने देश में हाशिए पर नज़र आ रहे हैं। यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि मानव शोषण के विरुद्ध सतत् वैश्विक संघर्ष के इतिहास में महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला मील के वे पत्थर हैं जो विश्व सभ्यता के इतिहास को स्वर्णिम बनाते हैं और हिंसा, संघर्ष व शोषण के विरुद्ध सक्रियता के परिचायक बन जाते हैं। प्रश्न है कि क्यों हम अब तक सत्य, अहिंसा, शांति, न्याय और समानता के मूल्यों को प्रत्येक नागरिक की जीवन शैली और व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बना पाए?

हिंसा और आक्रामकता को मौन स्वीकृति मिलने से संस्थागत ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि हिंसा का माहौल ख़त्म हो और भारतीय समाज शांतिपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा बन सके। ऐसे कौन से विकल्प हैं जो समाज को भय और हिंसा मुक्त बनाने में सक्षम हैं, यह विचारणीय विषय है। इसके साथ ही यह भी सोचना होगा कि समाज को हिंसा मुक्त बनाने में शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? समाज में फैलती हिंसा की संस्कृति को वैधता न मिले, इसके लिए कौन से प्रयास किए जाएं? ये ऐसे अहम प्रश्न हैं जिन पर सामूहिक चिंतन की तत्काल आवश्यकता है।

शेष.... दुनिया की ईवी कैपिटल बनेगी दिल्ली

पानी, अच्छी शिक्षा, सस्ती बिजली और विभिन्न तरीक़े की अन्य सुविधाएं मिल सकें, इसी को लक्ष्य बनाकर हम काम करते हैं।

प्रश्न:- लोगों को परिवहन सेवा उनके घर के पास मिले, इसको लेकर किस तरह की योजना है..?

उत्तर:- दिल्ली सरकार बसों की संख्या लगातार बढ़ा रही है। हमारा लक्ष्य है कि किसी भी व्यक्ति को उसके घर से अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर परिवहन की सेवा ज़रूर मिले। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक है और इसे हम पूरा कर रहे हैं।

प्रश्न:- रीजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में फेसलेस सर्विस शुरू हो गई है, कैसे परिणाम सामने आ रहे हैं..?

उत्तर:- ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हो या फिर अन्य किसी तरीके का काम हो, आरटीओ दफ्तर जाए बिना लोग सारे काम करवा रहे हैं। फेसलेस सर्विस शुरू की गई तो हमने भी नहीं सोचा था कि परिणाम इतना अच्छा आएगा। करीब 68,000 लोगों ने ऑनलाइन सर्विस का उपयोग करते हुए प्राइवेट लर्निंग लाइसेंस बनवाया। इसमें विशेष बात यह है कि जो भी व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस बनवाता है उसकी फोटा को कंप्यूटर उनके आधार कार्ड पर लगी फोटो से मैच कराता है, उसके बाद लाइसेंस बनता है।

प्रश्न:- आम आदमी पार्टी पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी सक्रिय है। चुनाव की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं, दिल्ली नगर निगम के भी चुनाव होने हैं किस तरह की उम्मीदें नज़र आ रही है..?

उत्तर:- दिल्ली में जिस तरीके अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है उसे पूरा देश देख रहा है और जिस तरह यहां पर शिक्षा व्यवस्था, है, परिवहन व्यवस्था है और उसके साथ बिजली पानी और अन्य सुविधाएं हैं, उन सभी चीज़ों को दूसरे प्रदेशों की जनता देख रही है। दिल्ली का केजरीवाल मॉडल हर जगह पसंद किया जा रहा है। निश्चित रूप से अन्य प्रदेशों में जब चुनाव होंगे तो वहां पर आम आदमी पार्टी को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। हमारी इच्छा यही है कि दिल्ली के साथ ही हम दूसरे प्रदेशों और पूरे देश में लोगों की सेवा कर सकें। जनता हमें इसके लिए मौक़ा दे।

शेष.... पाकिस्तान में फौजी चौधाराहट...

ख़ान को फौज और न्यायपालिका का बेशर्म गठबंधन ही सत्ता में लाया था और यह भी सही है कि उनके मंत्रियों को हर दूसरे दिन प्रेस के सामने दावा करना पड़ता था कि सरकार और सेना एक ही पेज पर हैं, पर हमें उस मानवीय कामना को भी याद रखना होगा, जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का सपना होता है कि उसे खुदमुख़्तार समझा जाए। विरोधी खुलेआम फिकरा कसते थे कि वह 'सेलेक्टड' प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान ख़ान की यह इच्छा अनुचित नहीं कही जाएगी कि उनकी कठपुतली प्रधानमंत्री की छवि बदले। कुछ माह पहले जनरल बाजवा ने पार्टी के बहाने देश के चुनिदां पत्रकारों के सामने एक लंबी फेहरिस्त रखी जब इमरान ख़ान ने उनकी बातें नहीं मानी थीं।

पाकिस्तान का मौजूदा संकट अभूतपूर्व है। दोनों पक्षों के मध्य सुलह कराने में लगे सरकारी प्रवक्ताओं ने दावा किया है कि अब तयशुदा फार्मूले के अनुसार, सेना मुख्यालय तीन नामों का एक पैनल भेजेगा और प्रधानमंत्री उन सभी का इंटरव्यू लेकर नया डीजी आईएसआई तय करेंगे। अपुष्ट समाचारों के मुताबिक, फौज ने इस प्रक्रिया से इंकार कर दिया है। विशेषकर से वे किसी नागरिक द्वारा अपने जनरलों का इंटरव्यू लेने की संभावना मात्र को ही अपने लिए अपमानजनक समझते हैं। इसके बाद इमरान ख़ान के पास विकल्प क्या है - पहला यह है कि जनरल बाजवा को बर्ख़ास्त कर दें और अपनी पसंद का दूसरा जनरल उनकी जगह लगा दे। पर कोई नहीं कह सकता कि बर्खास्तगी पर ऊंट जहांगीर करामत या परवेज़ मुशर्रफ, किस करवट बैठेगा। दूसरा विकल्प है कि कोई सम्माजनक बहाना ढूंढकर वह सेना के दिए नाम पर मोहर लगा दें। अधिकतर राजनीतिक पंडित सहमत हैं कि सारे नाटक के बावजूद इमरान ही अंतत: झुकेंगे।

दुर्भाग्य से नवाज़ शरीफ़ समेत सारा विपक्ष इमरान का मज़ाक उड़ाते हुए सेना के साथ खड़ा दिख रहा है। सेना ने इसी फूट का फायदा उठाकर सिविल हुकूमतों को हमेशा कमज़ोर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और पिछले तानाशाह परवेज़ मुशर्रफ़ की दुर्दशा की स्मृति शायद जनरल बाजवा को किसी दुस्साहस से रोक दे, पर झुकने के बाद इमरान और कमज़ोर होंगे और तब फौज बिना तख़्ता पलट ही वह सब हासिल कर लेगी, जिसकी ख़्वाहिश पाकिस्तानी समाज में वह करती रहती है।

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **01 Nov.2021** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र **मीम.सीन.जीम**

न्यायपालिका का बुनियादी ढाँचा
चिकित्सा सेवा में विस- तार

न्यायपालिका का बुनियादी ढाँचा

देश के क़ानूनी तंत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार और इसके रख रखाव अस्थाई और अनियोजित करके तरीक़े से किए जाने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने नाराज़गी ज़ाहिर की है। न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे में सुधार का मुद्दा कई सालों से चला आ रहा है। हालांकि अदालतों की समस्याएं कभी कभार ही सामने आती हैं। देश की अदालतों में आधारभूत संरचनाओं और प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी और बढ़ते संरचना निगम स्थापित करने की आवश्यकता जताई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की जिला और निचली अदालतें ब्रिटिशकालीन है। उनमें ज़रूरी सुविधाओं का अभाव है। न तो वादियों और प्रतिवादियों के लिए बैठने की जगह है और न ही वकीलों के लिए। इन अदालतों में महिला वकीलों के लिए ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं ही नहीं हैं। अनेक अदालतों की इमारतें झर्जर हो चुकी हैं। ऐसी ख़बरें सामने आती रही हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक गेस्ट हाउस में चलता रहा। कुछ न्यायाधिकरण अस्थबलों में चलते रहे। ग्रामीण अदालतों के पास स्टेशनरी नहीं। इनकी हालत तो गांवों के प्राथमिक स्कूलों से भी बदतर हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी अखिल भारतीय न्यायिक अधिकारी संगठन बनाम भारत संघ कई मामले सामने आए, जिन्होंने करोड़ों केसों का भार ढो रही सहायक न्यायपालिका की खस्ता हालत को जगज़ाहिर किया था। कभी अदालतें कुछ पहलुओं का अध्ययन करने के लिए न्यायाधीशों या क़ानून विशेषज्ञों की समिति का गठन करती रहीं हैं। इनकी रिपोर्ट भी विधि मंत्रालय को भेजी जाती रही हैं लेकिन यह भी लम्बित पड़ी अन्य फाइलों के ढेर में खो जाती रही हैं। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने पिछले दिनों यह भी कहा था कि जिन्होंने अदालतों के लिए ज़रूरी बुनियादी संरचनाओं के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और इसे वह जल्द ही विधि एवं न्याय मंत्री को सौंप देंगे। अब उन्होंने यह रिपोर्ट विधि मंत्रालय को भेज दी है। उम्मीद जताई जानी चाहिए कि रिपोर्ट में प्रस्तावित नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

अभी तक यह एक धारणा है कि देश की अदालतें पुराने ढांचे पर ही चलती हैं। ऐसे लचर ढांचे में पूरी क्षमता और असरदार ढंग से काम करना मुश्किल होता है। अदालतों के

> **अगर अदालतों का ढांचा ही दुरुस्त नहीं होगा तो लंबित मामलों और निपटाए जाने वाले मुकदमों की खाई नहीं पार सकते। देश में सिर्फ 54 फीसदी अदालतों में ही पीने के साफ पानी की व्यवस्था है। केवल पांच प्रतिशत कोर्ट परिसरों में ही चिकित्सा की सुविधा है। अलग से रिकॉर्ड रूम तो सिर्फ 32 प्रतिशत अदालतों में है। अभी तक सिर्फ 27 फीसदी कोर्ट में ही जजों की टेबल पर कम्प्यूटर लगे हैं।**

ढांचागत विकास से न्याय के लिए गुहार लगाने वाले फरियादियों की पहुंच आसान होती है। न्याय की राह आसान होती है। अदालतों को भी आर्थिक रूप से स्वायत्त होना चाहिए। अगर अदालतों का ढांचा ही दुरुस्त नहीं होगा तो लंबित मामलों और निपटाए जाने वाले मुकदमों की खाई नहीं पार सकते। देश में सिर्फ 54 फीसदी अदालतों में ही पीने के साफ पानी की व्यवस्था है। केवल पांच प्रतिशत कोर्ट परिसरों में ही चिकित्सा की सुविधा है। अलग से रिकॉर्ड रूम तो सिर्फ 32 प्रतिशत अदालतों में है। अभी तक सिर्फ 27 फीसदी कोर्ट में ही जजों की टेबल पर कम्प्यूटर लगे हैं। 73 फीसदी जजों की टेबल पर तो फाइलों का अंबार नज़र आता है। मानसून के दिनों में जिला अदालतों और ग्रामीण अदालतों की छतें टपकने लगती हैं। अदालत परिसरों में पानी खड़ा हो जाता है और कामकाज ठप्प हो जाता है। जिस तरह बजट में हर मद के लिए धन का वार्षिक आवंटन किया जाता है उसी तरह न्यायिक तंत्र के लिए भी बजटीय आवंटन किया जाता है उसी तरह न्यायिक तंत्र के लिए भी बजटीय आवंटन होना चाहिए। देशभर में उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में जजों की भारी कमी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम लगातार नामों की सिफारिश कर रही है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को ही देख लीजिए। जजों के 85 पद मंज़ूर होने के बावजूद केवल 45 जज कार्यरत हैं। हाईकोर्ट को इस समय 40 जजों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। जिसके चलते लोगों को तारीख़ पर तारीख़ मिल रही है। जजों की कमी के चलते पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लम्बित मामलों की संख्या 4 लाख तक पहुंच गई है। जजों की कमी की सूचि में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले स्थान पर है। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत धीमी है।

देश में जजों के 1098 स्वीकृत पद हैं, इनमें से 471 पद रिक्त पड़े हैं जो कुल पदों का करीब 43 प्रतिशत है। सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए समयबद्ध प्रक्रिया तय करनी चाहिए। समस्याएं और भी हैं अगर कॉलेजियम जिन लोगों के नाम बतौर जज नियुकित के लिए भेजती है तब उनके ख़िलाफ़ झूठी या सच्ची शिकायतों को भेजने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो उनके पर स्वीकृति की प्रक्रिया में देरी का बड़ा कारण बनता है।

जजों की नियुक्ति बहुत सोच समझ कर की जाती है इसलिए समय तो लगता ही है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम तब तेजी से जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश कर रहा है और सरकार उन नामों को स्वीकृति भी दे रही है। लंबित केसों के बोझ के बावजूद न्याय पालिका हर स्तर पर ऐतिहासिक फैसले दे रही है और देश के लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर क़ायम है। न्यायाधीशों ने समय-समय पर ऐसे फैसले दिए हैं जो हमेशा के लिए नज़ीर बन गए हैं। न्यायिक तंत्र के बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए। अभी तक अदालतों ढांचागत विकास और सुविधाएं अस्थाई और अनियोजित ढंग से ही उपलब्ध कराई गई। अब ज़रूरत है कि नेशनल जूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथारिटी बने जो अदालतों की ज़रूरतों को देखकर योजनाबद्ध तरीक़े से काम करें।

चिकित्सा सेवा में विस्तार

अपने देश में चिकित्सा सेवा का विस्तार सुखद और स्वागतयोग्य है। इसमें भी अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य

> **उत्तर प्रदेश में न केवल चिकित्सा की पढ़ाई, बल्कि चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सकों की संख्या का बढ़ना अनिवार्य है। जुलाई माह तक देश में 558 मेडिकल कॉलेज सेवाएं दे रहे थे, जिनमें से 289 सरकारी और 269 ग़ैर सरकारी थे,अलग अलग चरण में नरेन्द्र मोदी सरकार के समय करीब 157 मेडिकल कॉलेज खुले हैं या उन्हें मंज़ूरी मिली है। आंकड़ों से साफ है कि निजी मेडिकल कॉलेज की संख्या ज़्यादा है**

में नौ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, जो ख़ुशी दोगुनी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 2,329 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इन मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है, जो सिद्धार्थ नगर, ऐटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और जौनपुर जिलों में स्थित हैं। कॉलेजों का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'नौ मेडिकल कॉलेज स्वस्थ भारत के सपनों को साकार करेंगे। ये राज्य के लोगों के लिए एक उपहार हैं।' वाक़ई इन मेडिकल कॉलेज के खुलने से उत्तर प्रदेश में अस्पताल सुविधा में लगभग 2,500 बिस्तर जुड़ जाएंगे। गौर करने की बात है कि ये ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में स्थित हैं, जहां चिकित्सा का ढांचा अपेक्षाकृत रूप से कमज़ोर हैं। कोरोना के समय भी हमने इन इलाकों में चिकित्सकीय ज़रूरतों को महसूस किया है। निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, लेकिन उससे आम समाज की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में न केवल चिकित्सा की पढ़ाई, बल्कि चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सकों की संख्या का बढ़ना अनिवार्य है। जुलाई माह तक देश में 558 मेडिकल कॉलेज सेवाएं दे रहे थे, जिनमें से 289 सरकारी और 269 ग़ैर सरकारी थे। अलग अलग चरण में नरेन्द्र मोदी सरकार के समय करीब 157 मेडिकल कॉलेज खुले हैं या उन्हें मंज़ूरी मिली है। आंकड़ों से साफ है कि निजी मेडिकल कॉलेज की संख्या ज़्यादा है, सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या निजी कॉलेजों से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज न सिर्फ किफायती दर पर चिकित्सक तैयारी करते हैं, बहुत किफायती दर पर चिकित्सा सेवा भी देते हैं। इसके अलावा निजी मेडिकल कॉलेज से पैसे खर्च करके डिग्री हासिल करने वाले चिकित्सकों पर कमाने का दबाव भी ज़्यादा रहता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या किसी भी राज्य के सामाजिक विकास के लिए बेहतर संकेतिक हो सकती है। केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश हर जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज खोलने के सपने के साथ आगे बढ़ रही है, तो स्वागत है। बेशक, विगत सालों में नए मेडिकल

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान
आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।
रक़म भेजने के तरीक़े:-
❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर
SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरर्ण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173